● वर्ष : 17 ● अंक : 233 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शनिवार 13 जून 2026

केंद्र की पूर्वोत्तर में बड़े बदलाव की तैयारी: 2027 तक हटेगा अफस्पा

असम-नागालैंड सीमा पर फिर शुरू होगा तेल-गैस उत्पादन

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो क्षेत्र में शांति और विकास की नई दिशा देंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक एक-दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) हटाया जाएगा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार, असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद वाले क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ा तेल और गैस उत्पादन फिर से शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस निर्णय के पीछे पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में आए उल्लेखनीय सुधार और उग्रवादी गतिविधियों में आई कमी को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न शांति समझौतों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति की बहाली संभव हुई है। अफस्पा के दायरे में लगातार की जा रही कटौती इसी प्रगति का प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि यदि कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बनी रहती है, तब अगले वर्ष तक अधिकांश क्षेत्रों से यह कठोर कानून हटा दिया जाएगा। वहीं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी दूसरी बड़ी घोषणा कर शाह ने बताया कि केंद्र सरकार तथा असम और नागालैंड की सरकारों के बीच सीमा विवाद वाले उस क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है, जो लंबे समय से विवाद और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तेल और गैस भंडार मौजूद हैं। उत्पादन शुरू होने के बाद, क्षेत्र की तेल उत्पादन क्षमता वर्तमान 1,000-1,500 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर करीब दस गुना तक पहुंच सकती है। इस परियोजना से न केवल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के ये कदम पूर्वोत्तर भारत को देश की विकास यात्रा में एक अधिक प्रभावी और गतिशील भूमिका निभाने में सक्षम बनाएंगे।

अमरनाथ यात्राः सुरक्षा और व्यवस्था पर अमित शाह की उच्चस्तरीय समीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, तीर्थयात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक और सेना प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अधिकारियों से यात्रा मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधों, निगरानी व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तैयारियों और तीर्थयात्रियों को उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष जोर दिया कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिले। सूत्रों के अनुसार, बैठक में यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की कड़ी निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, मौसम संबंधी चुनौतियों और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समन्वित कार्ययोजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

सुप्रीम कोर्ट भी सीट चोरी में शामिल? जनता की अदालत में जाएगी कांग्रेस

राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किया है। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के तीन राज्य सभा के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके पहले मीनाक्षी नटराजन द्वारा चुनाव अधिकारी द्वारा उनके नामांकन को निरस्त करने के मामले में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई। किंतु उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर शुक्रवार को निरस्त कर दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। चुनाव अधिकारी द्वारा महेश केवट को निर्वाचित घोषित कर दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करने की बात कहकर याचिका का निराकरण कर दिया है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और निवृत्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। इस सीट चोरी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट भी साजिश में शामिल हैं। इस तरह का आरोप पहली बार किसी राजनेता द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर लगाया गया है। एसआईआर के मामले में लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही सुनवाई शुरू हो गई थी। सुनवाई के दौरान कई विधानसभाओं के चुनाव हो गए। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, उसे विधि विशेषज्ञों द्वारा आधा अधूरा बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने करीब 6.50 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल में लाखों मतदाताओं ने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कह दिया, इस बार यदि मतदान नहीं कर पाएंगे, तो अगली बार कर देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो परिणाम आए हैं। उसमें एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग किए गए। चुनाव आयोग द्वारा कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। चुनाव आयोग किसी आपत्ति का जवाब नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए 6.50 करोड़ लोगों के मतदान के अधिकार छिन गए, इसे वोट चोरी से जोड़ा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के चुनाव में गलत तरीके से नामांकन निरस्त कर भाजपा उम्मीदवार महेश केवट को चुनाव जिताने के लिए जो साजिश रची गई, उस साजिश में सुप्रीम कोर्ट शामिल है, यह कहकर भारतीय न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ कांग्रेस इस मामले को लेकर न्यायपालिका के स्थान पर जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कह रही है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए यह सबसे चिंताजनक स्थिति है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्नः घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर सीधी चर्चा

नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आयोजित चार दिवसीय महानिदेशक (डीजी) स्तर की महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में सीमा पर बढ़ते तनाव, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों पर हमलों और सीमा बाड़ को क्षति पहुंचाने जैसी घटनाओं पर चर्चा की गई। यह 57वां महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन था, जो नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में बार्डर सिक्योरिटी फार्स (बीएसएफ) और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशकों के बीच आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया, जबकि बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीजीबी के महानिदेशक मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी ने की। वार्ता के दौरान भारत ने सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमलों, तथा सीमा पर लगी बाड़ को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से उठाया। बीएसएफ प्रमुख कुमार ने इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ संबोधित कर सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अनिवार्यता पर जोर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप का दावा- यूरोप में फाइनल होगी समझौते की डील

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी गंभीर सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, जो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हालांकि, इस समझौते का श्रेय लेने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान को झटका देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान की धरती पर नहीं होंगे, बल्कि इस अंतिम डील को यूरोप में फाइनल किया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने और इसका क्रेडिट लेने के प्रयास कर रहा था, और वहां पहले भी एक दौर की वार्ता पूरी तरह विफल हो चुकी थी। इस बीच, जहां ट्रंप इस समझौते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं ईरान ने फिलहाल अमेरिकी दावे को सिरे से खारिज करते हुए ऐसी किसी भी डील से इनकार किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई इस समझौते के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं, तो ट्रंप ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि ईरानी नेतृत्व का जवाब हां में ही है। ट्रंप के मुताबिक, इस नए समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और परमाणु हथियारों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए राजी हो गया है।

वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को लेकर अमेरिका दूतावास के प्रभारी राजनयिक तलब

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय में शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजनयिक जेसन मीक्स को ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के लगातार हमलों के संबंध में तलब किया गया। मंत्रालय ने नागरिक जहाजों पर घातक बल प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की और स्पष्ट कहा कि ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं। एक दिन पहले एक बार फिर एक भारतीय चालक दल वाले जहाज को अमेरिकी नौसेना की ओर से निशाना बनाया गया। इस संबंध में आज अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजनयिक को तलब किया गया। राजनयिक करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मंत्रालय ने नागरिक जहाजों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग पर एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की। उनसे कहा गया कि ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं और एक संवेदनशील क्षेत्र में कठिन समय में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रभारी से कहा गया कि वे अपने अधिकारियों को भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेनाएं नागरिक जीवन की हानि को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। उल्लेखनीय है कि पिछले चार दिनों में तीन बार भारतीय चालक दल वाले तीन जहाजों को लाल सागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की ओर से निशाना बना जा चुका है।

एमआरपी व्यवस्था में लाई जाए पारदर्शिता, ग्राहकों को पता रहे उत्पादन लगात : नारायणभाई शाह

एजेंसी। नई दिल्ली

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के देश भर से आए कर्यकर्ताओं ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शुक्रवार को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। मंच से ग्राहक पंचायत ने अपने कार्यकर्ताओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा एमआरपी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया। जंतर मंतर पर आज आयोजित धरने में देश के विभिन्न राज्यों से आए उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित करीब 500 लोगों ने भाग लिया। एमआरपी की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आयोजित धरने में अपने संबोधन में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शाह ने कहा कि एमआरपी व्यवस्था का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को मनमानी कीमतों से बचाना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में खामियां है। उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसी वस्तु की वास्तविक लागत क्या है और उस पर कितना लाभ जोड़ा गया है। सरकार को इस संबंध में तुरंत कोई व्यवस्था या कानून बनाना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों का यूं ही कब तक हनन होता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव जयंतभाई कथिरिया ने कहा कि एमआरपी के विषय पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान कई मंत्रियों तक मांगे रखी गई। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज यह धरना सरकार को जगाने के लिए किया गया है ताकि नीति निर्धारकों तक ग्राहकों के हितों के बात पहुंचाई जा सके।

गोविंदपुरी में पांच मंजिला इमारत में आग तीन की मौत, पांच लोगों को बचाया गया

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बीती देर रात एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग ने तीन लोगों की जान ले ली। जबकि पांच लोगों को धुएं और आग के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में दो अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ हेमंत तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि 11 और 12 जून की दरम्यानी रात करीब 2:24 बजे गोविंदपुरी थाना पुलिस को तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां और कैट्स एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंचीं। आग लगने के बाद पूरी इमारत धुएं से भर गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। पुलिस, दमकल कर्मियों और बचाव दल ने संयुक्त अभियान चलाकर धुएं में फंसे आठ लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सफदरजंग अस्पताल तथा एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा। पुलिस के बताया कि हादसे में एक 22 वर्षीय युवक और दो महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं दो अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पीएम मोदी के पास समारोह में शामिल होने का समय है, अमेरिकी हमले की निंदा का नहीं

नई दिल्ली। ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय की मौत के बाद देश में सियासत गरमा गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के पास समारोहों में शामिल होने के लिए तो समय है, लेकिन अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों की मौत की निंदा करने का समय नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नागरिकों और नाविकों की जान की रक्षा करने में बार-बार विफल साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीयों की जान बचाना सरकार का पहला कर्तव्य है। यह दुखद और व्यथित करने वाला है कि पीएम मोदी के पास समारोहों के लिए समय है लेकिन भारतीयों की जान लेने के लिए अमेरिकी सेना की निंदा करने का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत के इतिहास में कभी इससे कमजोर सरकार रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अब भी भारतीयों को सैनिकों के रूप में भर्ती कर रहा है ''जो कई मारे जा रहे हैं'' लेकिन सरकार असहाय है।

अनुशासनहीनता मात्र पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता कर्मचारीः सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी कर्मचारी को केवल अनुशासनहीनता, आदेशों की अवहेलना या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश न मानने के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी जैसी कठोर सजा केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए, जहां भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, वित्तीय अनियमितता या नियोक्ता को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें साबित हों। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कार्यस्थल पर अनुशासन का महत्व निर्विवाद है, लेकिन अनुशासनहीनता के हर मामले में नौकरी से निकालना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार, अवैध लाभ प्राप्त करना, फंड का दुरुपयोग, संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या नियोक्ता को प्रत्यक्ष क्षति पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों के अभाव में कर्मचारी को सेवा से हटाना अत्यधिक कठोर कदम होगा। अदालत के अनुसार, किसी भी सजा का संबंध कर्मचारी के कृत्य की गंभीरता, उसके पूर्व सेवा रिकॉर्ड, परिस्थितियों और संस्थान पर पड़े प्रभाव से होना चाहिए। यह टिप्पणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी को वर्ष 2017 में सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए की गई। अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी कर्मचारी और नियोक्ता के संबंधों को स्थायी रूप से समाप्त कर देती है तथा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति और अन्य सेवा लाभों से भी वंचित कर देती है। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे निर्णयों का प्रभाव केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य भी प्रभावित होता है।

अब अपने दोस्त रूस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत

एजेंसी। नई दिल्ली

रक्षा निर्यात में नई दिल्ली लगा रही बड़ी छलांग

भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से विकसित हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब वापस रूस को ही बेची जा सकती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने स्पष्ट किया है कि यदि मॉस्को की ओर से इस मिसाइल को लेकर कोई ऑर्डर आता है, तो कंपनी उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस अचूक मिसाइल को भारत ने अपनी सैन्य संप्रभुता और सामरिक ताकत का मुख्य स्तंभ बनाया है, वह अब रूस की थलसेना और नौसेना के शस्त्रागार की भी शोभा बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय नौसेना प्रदर्शनी 'फ्लीट-2026' के दौरान ब्रह्मोस एयरोस्पेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और वे रूस की सैन्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का एक संयुक्त उपक्रम है। दोनों देशों ने साल 1995 में मिलकर ब्रह्मोस एयरोस्पेस की स्थापना की थी। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर इस घातक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया था, जिसे आज दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। जमीन, हवा और समुद्र—तीनों ही प्लेटफॉर्म से दागी जा सकने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता और सटीकता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना लंबे समय से इसका सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ एक विशेष सैन्य ऑपरेशन के दौरान भी इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर इसकी मांग में भारी उछाल आया है।

वर्तमान में भारत एक बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक फिलीपींस बना, जिसके साथ साल 2022 में 37.5 करोड़ डॉलर का सौदा हुआ था। इस समझौते के तहत मिसाइलों की खेप सफलतापूर्वक पहुंचाई जा चुकी है। फिलीपींस के बाद हाल ही में भारत ने वियतनाम को भी ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति करने की आधिकारिक पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में हुए एक बड़े रक्षा संवाद के दौरान अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इंडोनेशिया के साथ भी मिसाइल आपूर्ति को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

भारतीय निशानेबाजी को बड़ा झटका, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज निशानेबाजी कोच और पूर्व स्टार शूटर जसपाल राणा का गुरुवार देर रात नई दिल्ली के साकेत स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय खेल जगत, विशेषकर निशानेबाजी समुदाय में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप से भारतीय दल के साथ लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उनका हृदय संबंधी उपचार हुआ था, जिसमें स्टेंट डाला गया था। निधन के समय वह भारत की पिस्टल निशानेबाजी टीम के उच्च प्रदर्शन कोच के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे प्रभावशाली नामों में गिने जाते थे। कोच के रूप में उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी थीं जिसने एक ही ओलंपिक में दो पदक हासिल किए।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि नामांकन पत्र खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर न तो उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है और न ही उच्चतम न्यायालय। ऐसे में ये याचिका खारिज की जाती है।सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई। सिंघवी ने कहा कि जिस आपराधिक मामले का जिक्र किया जा रहा है उसमें अभी संज्ञान भी नहीं लिया गया है। नटराजन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत संज्ञान लेने से पहले का समन जारी किया गया है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33ए के मुताबिक उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा करना है जिनमें संज्ञान लिया जा चुका है।मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निर्वाची अधिकारी अरविन्द शर्मा ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने अपने खिलाफ तेलंगाना में लंबित आपराधिक मामले का खुलासा नामांकन पत्र में नहीं किया। मध्यप्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर 11 जून को निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी गयी। तीनों सीटें भाजपा के उम्मीदवारों ने जीती हैं।

पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का फैसला स्वागतयोग्यः तरुण चुग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हरियाणा सरकार द्वारा 8वीं कक्षा के इतिहास के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के जीवन, योगदान और उनकी शिक्षाओं को शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने कहा कि यह पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिख विरासत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने जहां गुरुओं के इतिहास को उपेक्षित किया, वहीं भाजपा ने वीर बाल दिवस, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम और अन्य आयोजनों के जरिए सिख इतिहास को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का कार्य किया है। चुग ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि 1984 का सिख कत्लेआम देश कभी नहीं भूल सकता। वोटर लिस्ट पकड़कर सिखों को ढूंढ-ढूंढकर मारा गया, गुरुद्वारे जलाए गए, 52 शहरों को श्मशान बना दिया गया। भोपाल गैस कांड से लेकर दंतेवाड़ा के शहीदों तक कांग्रेस के दोहरे मापदंड जगजाहिर हैं। कांग्रेस की हिमालयन मिस्टेक्स की सूची बहुत लंबी है। जनता झूठ, भ्रम और मगरमच्छी आंसुओं की राजनीति को बार-बार नकार चुकी है। यह दाल अब गलने वाली नहीं है।तृणमूल कांग्रेस पर तंज कसते हुए तरुण चुग ने कहा कि जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट मनी का राजनीतिक अड्डा बना दिया था उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं।

फिरोजाबाद स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव के मामले में दो गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के निकट लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन संख्या 12003 लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर 11 जून को शाम करीब 7:18 बजे उस समय पथराव हुआ, जब ट्रेन प्रयागराज मंडल के अंतर्गत फिरोजाबाद स्टेशन के पास पहुंच रही थी। रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की। स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, पथराव की घटनाओं को रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाता है।उल्लेखनीय है कि गुरुवार देर शाम मक्खनपुर और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच पैमेश्वर गेट के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाया था। घटना के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी ट्रेन के ई-1 कोच में यात्रा कर रहे थे। हालांकि इस घटना में उन्हें या किसी अन्य यात्री को कोई चोट नहीं आई। ट्रेन के टुंडला स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ टीम ने कोच का निरीक्षण किया, जिसमें केवल बाहरी शीशा क्षतिग्रस्त पाया गया। घटना के बाद पुलिस, एलआईयू और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस की सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एआई मिशन का बड़ा कदम, स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल 'वर्या' लॉन्च

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारत कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) मिशन के सहयोग से एआई कंपनी अवतार ने शुक्रवार को स्वदेशी वीडियो जनरेशन मॉडल 'वर्या' लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बेहद कम लागत और कम समय में तैयार कर सकता है। लॉन्च कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन भी मौजूद रहे। वर्या को भारत एआई मिशन के तहत उपलब्ध कराए गए कंप्यूटिंग संसाधनों की मदद से विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वर्या वीडियो बनाने की प्रक्रिया को 50 चरणों से घटाकर केवल 4 चरणों में पूरा करता है। इससे वीडियो निर्माण की लागत घटकर लगभग 48 पैसे प्रति सेकंड रह जाती है, जो कई वैश्विक एआई वीडियो मॉडलों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक किफायती बताई जा रही है।वर्या को भारतीय जरूरतों और विविधताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भारतीय त्योहारों, संस्कृति, खान-पान, पहनावे और स्थानीय परिवेश को समझते हुए वीडियो तैयार करने में सक्षम है। शिक्षा, ई-कॉमर्स, विज्ञापन, सरकारी जनजागरूकता और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग की संभावना है।इस अवसर पर सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि वर्या भारत की स्वदेशी एआई क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह देश के गहरे तकनीकी नवाचार को नई गति देगा। वहीं, अवतार के सह-संस्थापक और सीईओ श्रवांत अलुरु ने कहा कि भारत में एआई का भविष्य केवल बड़े मॉडल बनाने में नहीं, बल्कि ऐसे कुशल और किफायती मॉडल विकसित करने में है जो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें।

मंजीत महाल, गोगी और रणदीप भाटी गैंग तक पहुंचते थे हथियार, स्पेशल सेल ने दबोचे 6 तस्कर

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले दो बड़े अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 26 अत्याधुनिक सेमी-आटोमैटिक पिस्टल, आठ कारतूस, तस्करी में इस्तेमाल स्विफ्ट, थार और आल्टो कारें, छह मोबाइल और कई सिमकार्ड बरामद बरामद किए गए हैं। ये लोग मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खरगोन से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली-एनसीआर के कुख्यात मंजीत महल, जितेंद्र उर्फ गोगी और रणदीप भाटी गिरोह के गुर्गों को सप्लाई करते थे।स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त नारा चैतन्य का कहना है कि एसीपी राहुल कुमार सिंह की टीम ने दो अलग-अलग आपरेशनों यह कार्रवाई की। पहले आपरेशन के तहत 22 मई को सेल की टीम ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (ताहिरपुर) के पास से रवि कुमार और सुनील तंवर को दबोच लिया गया। इनके बैग की तलाशी लेने पर 15 अवैध पिस्टल (10 रवि से और पांच सुनील से) बरामद हुईं। पूछताछ में पता चला कि रवि, सुनील के कहने पर एमपी से हथियार लाया था। इसके बाद 24 मई को इनकी निशानदेही पर हथियारों के रिसीवर योगेश को द्वारका सेक्टर-सात से गिरफ्तार किया गया। उसकी गाड़ी के गुप्त केबिन (कैविटी) से चार पिस्टल और पांच कारतूस मिले। तीनों से पूछताछ के बाद 26 मई को पुलिस टीम ने दो और रिसीवर रजत उर्फ रज्जू और सौरभ को लक्ष्मी नगर से गाड़ी सहित दबोच लिया। इनके पास से दो पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए। दूसरे आपरेशन में 22 मई को स्पेशल सेल की टीम ने एक और समानांतर कार्रवाई करते हुए रोहिणी हेलीपैड के पास न्यू कोंडली के रहने वाले हथियार सप्लायर निखिल को दबोच लिया। वह एक बदमाश को हथियारों की एक बड़ी खेप देने आया था। उसके पास से पांच पिस्टल बरामद की गई।इनमें सुनील तंवर उर्फ चीनू, बागपत का रहने वाला है। इसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। यह कुख्यात अपराधी अंकित गुर्जर (मृत) का भतीजा है। यह फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में लिप्त रहा है। चाचा की मौत के बाद इसने हथियार तस्करी का नेटवर्क संभाल लिया।रवि कुमार, लोनी का रहने वाला है। 2015 में जीटीबी एन्क्लेव से एक युवक के अपहरण और हत्या मामले में वह जेल गया था। जेल में अपराधियों के संपर्क में आकर बाहर निकलने के बाद दो साल से हथियार तस्करी करने लगा था।योगेश, द्वारका का रहने वाला है और चार मामलों में शामिल रहा है। वह पहले दूध की डेयरी चलाता था। 2024 में सुनील तंवर के संपर्क में आकर इसने गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने लगा। इसपर हत्या के प्रयास और लूट के मामले दर्ज हैं। रजत उर्फ रज्जू, लोनी का रहने वाला है और हत्या, लूट और चोरी जैसे 19 मामलों में शामिल रहा है। जेल में सुनील तंवर से मुलाकात के बाद यह भी हथियार तस्करी करने लगा था। सौरभ, बागपत का रहने वाला है और 17 मामलों में शामिल रहा है। जेल में इसकी रजत से दोस्ती हुई। इसके बाद गांव में अपनी दुश्मनी और दबदबा कायम करने के लिए इसने हथियार खरीदे थे। निखिल, न्यू कोंडली का रहने वाला है और चार मामलों में शामिल रहा है। अप्रैल में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इसने एमपी से हथियार लाकर दिल्ली में बेचने लगा।

जमाअत के अध्यक्ष ने कमर्शियल जहाज़ पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत की कड़ी निंदा की

- जवाबदेही की मांग और भारत सरकार से कड़े कूटनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ओमान तट के पास कमर्शियल टैंकर 'सेटेबेलो' पर अमेरिकी सेना के हमले की कड़ी निंदा की है जिसमें तीन भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भारतीय क्रू सदस्यों वाला तीसरा जहाज़ है जिस पर हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने हमला किया है। बेगुनाह लोगों की जान जाने पर गहरा दुख जताते हुए सैयद सआदुल्लाह हुसैनी ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस मुश्किल समय में उनके लिए साहस और धैर्य की प्रार्थना की। हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के जहाज़ को निशाना बनाने और भारतीय नागरिकों की हत्या को 'कोलेटरल डैमेज' कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। व्यावसायिक समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवन-रेखा के समान महत्वपूर्ण हैं और सैन्य अभियानों से आम नागरिकों के तौर पर समुद्री क्षेत्र में काम करने वालों की जान कभी भी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी हरकतें मानवीय सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन हैं, अंतरराष्ट्रीय नियमों को कमजोर करती हैं और पूरे क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हैं।

फोर्टिस गुरुग्राम ने मायलोमा और लिंफोमा के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया

- प्रिसीजन ब्लड कैंसर केयर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति
- अपनी तरह के इस पहले सेंटर में प्रिसीजन डायग्नॉस्टिक्स, जिनोमिक्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सैलुलर थेरेपी और पर्सनलाइज्ड केयर से ब्लड कैंसर के परिणामों पर होगा सकारात्मक असर

लोकतंत्र की शान

गुरुग्राम : फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मायलोमा एंड लिंफोमा का शुभारंभ किया है। इस पहल के माध्यम से ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए स्पेश्यलाइज़्ड, मरीज-केंद्रित और शोध-आधारित देखभाल प्रदान की जाएगी। इस केंद्र को "सन डिजीज़ वन डॉक्टर, वन फोकस" के सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जहां विशेषज्ञों के अलावा एडवांस डायग्नॉस्टिक क्षमताओं, इनोवेटिव थेरेपी, प्रिसीजन मेडिसिन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, सैलुलर थेरेपी, क्लीनिकल रिसर्च तथा व्यापक मरीज सपोर्ट सेवाओं को एक ही एकीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। देश में रोग विशेष पर केंद्रित अपनी तरह के इस पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मायलोमा एंड लिंफोमा की स्थापना ब्लड कैंसर केयर की बढ़ती जटिलताओं को ध्यान में रखकर की गई है जहां पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट के अलावा विभिन्न विभागों के बीच परस्पर तालमेल का लाभ मरीजों को मिलता है। यह पहल क्लीनिकल परिणामों में सुधार लाने के अलावा इनोवेशन तक एक्सेस बढ़ाएगी, ट्रांसलेशनल रिसर्च को मजबूती देगी और साथ ही, मायलोमा एवं लिंफोमा मैनेजमेंट के भी नए मानक रचेगी।

डाक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा

- 20 जुलाई से शुरू होगा चरणबद्ध संघर्ष
- 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
- रेल डाक सेवा बहाल करने और रिक्त पद भरने की मांग
- परामर्शदाता संस्थाओं की सिफारिशों के जरिए निजीकरण का आरोप

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विभागीय नीतियों के संबंध में अपनी चिंताओं को सामने रखते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। महासंघ के महासचिव अनंत कुमार पाल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन का मानना है कि कुछ नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थागत बदलावों से कर्मचारियों के हितों तथा डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। अनंत कुमार पाल ने कहा कि डाक विभाग में लागू की जा रही कुछ सुधारात्मक प्रक्रियाओं और परामर्शदाता संस्थाओं की सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों के बीच आशंकाएं हैं। उनका कहना है कि विभिन्न बचत योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार और दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रेस वार्ता में महासंघ के पूर्व महासचिव एवं संरक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मेल मोटर सेवा तथा सिविल विंग से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तनों और विभिन्न संवर्गों के प्रस्तावित विलय को लेकर कर्मचारियों में चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक संवाद की आवश्यकता है। अनंत कुमार पाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ देश की सार्वजनिक डाक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार और डाक प्रशासन कर्मचारियों की चिंताओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

गोवा में वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन 15 जून को

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 जून को गोवा में वैश्विक पवन दिवस-2026 सम्मेलन का आयोजन करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी भारत की पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाले इस समारोह का नेतृत्व करेंगे।मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून को गोवा में पवन ऊर्जाः महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक विषय पर वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत अभी विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट के लक्ष्य के साथ भारत के 2070 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण है।मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में सरकार, नियामकों, विकासकर्ताओं, विनिर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ पूर्ण सत्र और पैनल परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि उपकरणों को स्थापित करने में तेजी लाने, क्रियान्वयन में सुधार और घरेलू क्षमता मजबूत करने के व्यावहारिक उपायों की पहचान की जा सके। इस क्षेत्र में विकास द्वितीय चरण में प्रवेश करने के साथ ही वैश्विक पवन दिवस 2026 का गोवा आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए भविष्य योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।मंत्रालय ने कहा कि इस सममेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी, मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ग्रिड इंडिया, प्रमुख राज्य सरकारों और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और इंडियन विंड पावर एसोसिएशन सहित उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

उत्तर-पश्चिम भारत को अगले कुछ दिनों के दौरान भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार एक तरफ उत्तर-पश्चिम भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलगी, वहीं दूसरी तरफ मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी के अनुसार राजधानी में शनिवार दोपहर या शाम के दौरान तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। यहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36-38 डिग्री सेल्सियस और 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 14 जून को दोपहर और शाम के दौरान आंधी-तूफान जैसी स्थिति बनने का अनुमान है। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37-39 डिग्री सेल्सियस और 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 15 जून को कुछ बादल छाए रहेंगे। यहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37-39 डिग्री सेल्सियस और 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून आज पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिम भारत में शनिवार तक बारिश होने की संभावना है। वहीं, 13 जून को मराठवाड़ा, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान, 13-16 जून तक विदर्भ के कुछ इलाकों में लू चलने की बहुत संभावना है।अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जगहों पर 13-18 जून के बीच मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसी बीच, इन क्षेत्रों में तेज रफ्तार हवाएं चलने और कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि होने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम भारत के अलावा 18 जून तक देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 13 जून को गर्म और उमस भरे मौसम की स्थिति रहने के आसार हैं। वहीं, 13 जून को ही विदर्भ के कुछ इलाकों में गर्म रात की स्थिति रहने की बहुत संभावना है।

भारत ने 'सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारत ने सामाजिक न्याय को लेकर वैश्विक गठबंधन (जीसीएसजे) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी), सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान जीसीएसजे की समन्वय समूह बैठक में भी भाग लिया।श्रम मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान करंदलाजे ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. होंगबो, बांग्लादेश, मोल्दोवा, ब्राजील और स्विट्जरलैंड के श्रम मंत्रियों, बेल्जियम के उप-मंत्री और अन्य प्रमुख सहयोगियों से भी मुलाकात की। इसके अलावा करंदलाजे ने 11 जून को जेनेवा में 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के दौरान आयोजित वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन (जीसीएसजे) के समन्वय समूह की बैठक में भाग लिया।करंदलाजे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन का समन्वय समूह के रिसेप्शन में आईएलओ के डीजी, बांग्लादेश, मोल्दोवा, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड के श्रम मंत्रियों, बेल्जियम के उप-मंत्री और अन्य सम्मानित सहयोगियों के साथ शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीसीएसजे के संस्थापक सदस्य के तौर पर भारत सभी के लिए बेहतर काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि भारत ने आईएलओ, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर गठबंधन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। भारत समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, जिम्मेदार व्यावसायिक कार्यप्रणालियों का समर्थन करने और न्यायसंगत एवं लचीले श्रम बाजारों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से गठबंधन के कार्य के अगले चरण में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए तत्पर है। उल्लेखनीय है कि करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 114वें अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। करंदलाजे ने आईएलसी के दौरान आयोजित वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के समूह की बैठक में भाग लिया।

संक्षिप्त समाचार

DIG अजय कुमार साहनी की अगुवाई में बरेली रेंज में 8 महीने में 98 पुलिस मुठभेड़, 175 बदमाश गिरफ्तार

जीरो टॉलरेंस नीति का असरः 129 अपराधी घायल

2 इनामी ढेर, 4.98 करोड़ की संपत्ति जब्त

लोकतंत्र की शान , (बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा), मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को बरेली परिक्षेत्र पुलिस ने बड़े स्तर पर लागू करते हुए पिछले आठ महीनों में लगातार अभियान चलाया। पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) अजय कुमार साहनी के निर्देशन में बरेली रेंज के चार जिलों—बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर—में 01 अक्टूबर 2025 से 31 मई 2026 तक अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 98 पुलिस मुठभेड़ हुईं, जिनमें 175 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान 129 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि दो इनामी अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। इन अभियानों में पुलिस बल को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 39 पुलिसकर्मी घायल हुए। DIG अजय कुमार साहनी ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

गंभीर अपराधों पर फोकस, वांछित अपराधियों पर शिकंजा– बरेली रेंज पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, गोवध, पॉक्सो और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 21 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

2017 बैच की टॉपर IAS सौम्या पांडेय बनीं बरेली विकास प्राधिकरण की VC, DM की रेस में अब भी इंतजार

जूनियर अफसर बने जिलाधिकारी, सौम्या पांडेय को मिली BDA और RFC की कमान; प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज

लोकतंत्र की शान , (बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा), उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2017 बैच की चर्चित IAS अधिकारी और अपने बैच की टॉपर सौम्या पांडेय को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) का उपाध्यक्ष (VC) नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (RFC), बरेली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस नियुक्ति के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां एक ओर उनके बैच के कई अधिकारी और कुछ जूनियर अफसर पहले ही जिलाधिकारी (DM) की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वहीं सौम्या पांडेय को अभी भी डीएम पद का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी नई पोस्टिंग को लेकर कई तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत निकाले जा रहे हैं।

BDA की कमान संभालेंगी सौम्या पांडेय, विकास योजनाओं पर रहेगा फोकस– बरेली विकास प्राधिकरण शहर की आधारभूत संरचना, आवासीय परियोजनाओं, मास्टर प्लान, अवैध निर्माण नियंत्रण और शहरी विस्तार जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालता है। ऐसे में सौम्या पांडेय की नियुक्ति को एक बड़े प्रशासनिक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। बरेली तेजी से विस्तार कर रहा शहर माना जा रहा है और यहां कई प्रमुख परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। ऐसे में नए नेतृत्व से योजनाओं की गति और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

DM नहीं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी– प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी IAS अधिकारी के लिए विकास प्राधिकरण जैसे संस्थान का नेतृत्व महत्वपूर्ण अनुभव माना जाता है। हालांकि आम तौर पर इस बैच के कई अधिकारी जिलाधिकारी की भूमिका में पहुंच चुके हैं, लेकिन सौम्या पांडेय को अभी अलग प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।

सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना

लोकतंत्र की शान, पैलानी /बांदा। थाना क्षेत्र के सिंधन कलां गांव में बेखौफ चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपये की नकदी और सामान साफ कर दिया। रात के अंधेरे में घर में घुसे चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर जमकर उत्पात मचाया और घर में रखी दो गुल्लकों को फोड़कर उसमें जमा करीब 40 हजार रुपये समेट ले गए। गुरुवार सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो घर में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सिंधन कलां गांव निवासी पीड़ित राजाराम पुत्र जागेश्वर ने बताया कि वह बुधवार की रात गांव के ही भूरा महाराज के ट्यूबवेल पर रखवाली करने गए थे। उनका पुत्र शिवबाबू रोजी-रोटी कमाने के सिलसिले में सूरत में रहता है, जबकि घर के बच्चे अपनी दादी के यहाँ सोने चले गए थे। घर को पूरी तरह सूना पाकर चोर रात में मकान की ऊंची दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने इसके बाद कमरे का ताला तोड़ा और पूरे घर के बक्से व सामान को खंगाल डाला।

मुरादाबाद डीएम का 'चेयर योग' चर्चा में, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/मुरादाबाद के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठकर योगाभ्यास कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डीएम बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ चेयर योग करते दिखाई दे रहे हैं। इस पहल को कार्यस्थल पर तनाव कम करने और कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस पहल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने इसे प्रशासन की सकारात्मक और नवाचारी पहल बताते हुए सराहा है, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि योग का वास्तविक उद्देश्य शरीर को सक्रिय और लचीला बनाना है, जिसके लिए मैदान या खुले स्थान पर नियमित योगाभ्यास अधिक प्रभावी माना जाता है। जानकारी के अनुसार डीएम राजेंद्र पैंसिया ने अधिकारियों को कार्य के दौरान होने वाले तनाव से राहत दिलाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से यह अभ्यास कराया। प्रशासन का मानना है कि व्यस्त कार्यालयी कार्य के बीच कुछ मिनट का योग कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। वायरल वीडियो के बाद शहर में योग की इस नई शैली पर चर्चा तेज हो गई है। आमजन का कहना है कि यदि अधिकारी स्वयं मैदान में उतरकर नियमित योगाभ्यास करें तो समाज में और अधिक सकारात्मक संदेश जाएगा। फिलहाल डीएम की यह पहल सोशल मीडिया और जनचर्चाओं का विषय बनी हुई है।

हर शहर, गांव को ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक सेवा से जोड़ेंगेः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी व सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विजन दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में हर शहर-गांव को पेट्रोल-डीजल मुक्त ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक सेवा से जोड़ेगी। हर व्यक्ति को बेहतर, आरामदायक व पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा मिलने पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में परिवहन विभाग का बेड़ा बड़ा हो रहा है, उनके कार्य भी बड़े दिखने चाहिए। सीएम योगी ने शुक्रवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों व 3 हाइड्रोजन बसों को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने इस अवसर पर नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया।

15 जून से संचालित होने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट –अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध बड़ी चुनौतियां हैं। इनके कारण दुनिया वायु प्रदूषण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि का सामना कर रही है। दुनिया पर थोपे गए युद्धों की कीमत पूरी मानवता चुका रही है। पीएम के विजन को धरातल पर उतारने के लिए 15 जून से भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक हब तथा सुचारु वायुसेवा की दृष्टि से यात्रियों, नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीनों अथॉरिटी (नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यीडा) ने परिवहन निगम के माध्यम से यह सेवा प्रारंभ की है। यह नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक़ की सबसे बुलंद आवाज़ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसीः चौधरी मुशीर अली खान

» 14 जून को बहराइच पहुंचकर ओवैसी की तकरीर सुनें, अपने अधिकारों और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हों एकजुट

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल। जनपद संभल के चेयरमैन पति एवं एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता चौधरी मुशीर अली खान ने 14 जून 2026 को बहराइच में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है।<चौधरी मुशीर अली खान ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की सबसे बुलंद आवाज़ बनकर उभरे हैं। संसद में जब भी मुसलमानों, दलितों और कमजोर तबकों के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठता है, तो बैरिस्टर ओवैसी पूरी मजबूती और बेबाकी के साथ उनकी पैरवी करते दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब की राजनीति का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को उनका संवैधानिक हक़ दिलाना है। उनकी आवाज़ लाखों-करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद, हौसले और इंसाफ़ का प्रतीक बन चुकी है। यही वजह है कि देशभर में युवा, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। चौधरी मुशीर अली खान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि 14 जून को बहराइच पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर सुनें और अपने अधिकारों, सम्मान तथा आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एकजुटता का परिचय दें। उन्होंने कहा कि यह जनसभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, बराबरी और संवैधानिक अधिकारों की आवाज़ को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग बहराइच पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे तथा इंसाफ़, तरक्की और भाईचारे के संदेश को और मजबूत करेंगे।

अखिलेश यादव की पुत्री पर अभद्र टिप्पणियों के विरोध में सपा का कड़ा रुख, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन

» दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग, विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव, सुहेल इकबाल, कृष्ण मुरारी शंखधार सहित कई सपा नेता रहे मौजूद

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल : बहजोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणियों के विरोध में समाजवादी पार्टी जिला संभल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, असत्य एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक मूल्यों और सम्मानजनक राजनीति में विश्वास रखती है। किसी भी व्यक्ति या परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणियां समाज में गलत संदेश देती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार, गुन्नौर विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव, संभल विधानसभा से विधायक पुत्र सुहेल इकबाल, प्रमोद यादव सहित समाजवादी पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान तथा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया है। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जिले में मजबूती के साथ जनता की आवाज़ उठाने का कार्य कर रही है।

एसपी संभल ने बढ़ाया हौसलाः थाना प्रभारी संजय सिंह, उप निरीक्षक रश्मि मलिक व हेड कांस्टेबल संदीप कुमार सम्मानित

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/ सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर लगभग 200 बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने तथा लूट की सनसनीखेज घटना का सफल खुलासा करने पर थाना हजरतनगरगढ़ी प्रभारी संजय सिंह, उप निरीक्षक रश्मि मलिक एवं हेड कांस्टेबल संदीप कुमार को पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में हजरतनगरगढ़ी पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ग्राम बराही में भूमाफियाओं के कब्जे से लगभग 200 बीघा सरकारी भूमि को मुक्त कराया। इस बड़ी कार्रवाई ने भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का काम किया और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित कराया। इसके साथ ही हाल ही में अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई लूट की घटना का भी हजरतनगरगढ़ी पुलिस ने सफल खुलासा किया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा लूटी गई धनराशि और संबंधित सामान बरामद कर घटना का पर्दाफाश किया। इस सफलता से पुलिस की कार्यकुशलता और अपराधियों पर मजबूत पकड़ का परिचय मिला। उप निरीक्षक रश्मि मलिक ने पूरे अभियान और अपराध के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सूझबूझ, लगन और कर्तव्यनिष्ठा के कारण पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वहीं हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने भी अपनी मेहनत, सतर्कता एवं समर्पण से दोनों अभियानों को सफल बनाने में अहम योगदान दिया।

पुलिस अधीक्षक संभल ने तीनों पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनहित, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी विभाग का गौरव हैं। उनके सम्मान से अन्य पुलिसकर्मियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने थाना प्रभारी संजय सिंह, उप निरीक्षक रश्मि मलिक एवं हेड कांस्टेबल संदीप कुमार को मिले सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हजरतनगरगढ़ी पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया। लोगों का कहना है कि इन अधिकारियों की सक्रिय कार्यशैली के कारण क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है तथा आमजन का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

बाबा विश्वनाथ व मां गंगा ने पीएम मोदी को दिया गरीबों की पीड़ा समाप्त करने का सामर्थ्यः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई महान व्यक्तित्व नेतृत्व करता है तो वह देश असुरक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर महान बनता है। देश का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी ने गरीबी देखी है, इसलिए बाबा विश्वनाथ व मां गंगा ने उन्हें गरीब की पीड़ा समाप्त करने की सामर्थ्य दी है। सीएम ने तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के बाद सपने हकीकत में बदल रहे हैं। जब संवेदनशील व्यक्तित्व नेतृत्व करता है तो संवेदना दिखती है। सीएम ने बाबा विश्वनाथ व मां गंगा से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री मोदी का यशस्वी नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिलता रहे। सीएम योगी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में काशीवासियों से संवाद किया।

बाबा विश्वनाथ धाम का हर व्यक्ति गौरवान्वित– सीएम ने कहा कि बाबा विश्वनाथ धाम का हर व्यक्ति अभिभूत व गौरवान्वित है, क्योंकि 12 वर्ष पहले नए भारत को नेतृत्व देने के लिए काशी ने सांसद के रूप में मोदी जी का चुनाव किया। सही चुनाव जनमानस को सम्मान दिलाता है। देश मोदी जी के निर्वाचित पीएम के रूप में नए रिकॉर्ड को लेकर उत्साहित है, ऐसे में उनके साथ काशी का नाम भी जुड़ता है।

अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद रामपुर का एक प्रतिनिधिमंडल पंडित सौरभ पाठक (जिला अध्यक्ष) के नेतृत्व में माननीय नगर विधायक आकाश सक्सेना से मिला

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुरः सिविल लाइन क्षेत्र में भगवान परशुराम चौक का निर्माण बहुत ही कम समय में पूरा करने एवं विधिवत लोकार्पण करने के उपलक्ष में अंग वस्त्र व एक प्रतीक चिह्न देकर धन्यवाद प्रेषित किया और ईश्वर से प्रार्थना की उनका यश दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता रहे !और साथ ही एक ज्ञापन दिया की रामपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 26503 / 26504 गोमती नगर-सहारनपुर जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव किए जाने के संबंध में जैसा की सर्वविदित है की जिला सीतापुर की तहसील मिश्रिख में नैमिषारण्य धाम स्थित है जो की सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था का स्थान है नैमिषारण्य से वर्ष भर अनेक साधु और महात्मा लोग रामपुर , बरेली व अन्य जिलों में कथा वाचन के लिए भ्रमण करते रहते हैं और अनेक श्रद्धालु वर्ष भर अपने-अपने साधनों से नैमिषारण्य में अनेको मंदिर के दर्शन करने लिए आते जाते रहते हैं अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके वंदे भारत ट्रेन जो की गोमती नगर से सहारनपुर जंक्शन जाती है और सीतापुर रूकती ही है उसका स्टॉपेज रामपुर में भी होना चाहिए अनेक और अनेक धर्म प्रेमियों की यही राय है जिससे वहां से आने जाने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को भ्रमण करने में सुविधा हो !इस ट्रेन का एक चिकित्सकीय लाभ भी मिलेगा डालीगंज जंक्शन(लखनऊ) रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर केजीएमयू मेडिकल कॉलेज स्थित है जो लोग केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करना चाहते हैं डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित केजीएमयू में अपना इलाज भी आसानी के साथ करा सकते हैं जनमानस की सुविधा को देखते हुए यह एक अति महत्वपूर्ण कदम रहेगा रामपुर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध ! ज्ञापन देते समय मोनिका शर्मा ,अनु मिश्रा ,अभिषेक शर्मा ,पुनीत शर्मा, पारस वशिष्ठ ,संदीप शर्मा ,पवन पाठक ,अनुभव वशिष्ठ ,शिवम शर्मा सात्विक भारद्वाज, रविंद्र शर्मा, अवनीत कुमार शर्मा,प्रशांत कुमार शर्मा, लव शर्मा, कुश शर्मा , यश शर्मा, नितिन शर्मा, आयुष शर्मा,मयंक शर्मा, सुखदेव मिश्रा, विकास शर्मा , ऋतुन्जय बंधु शर्मा, गोपाल शर्मा ,नूतन शर्मा उपस्थित रहे

रामपुर सरकारी स्कूल के मैदान से हटाई जाएंगी 3 मजारे

» शिक्षा विभाग द्वारा परिजनों को नोटिस भेजकर अवगत कराया गया जिला अधिकारी बोले अतिक्रमण हटेगा

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमारशर्मा

मंडल मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/रामपुर के चमरोआ ब्लॉक ग्राम भमरौआ में सरकारी स्कूल के मैदान से तीन मजारों को हटवाने की प्रक्रिया तेजी हो गई है। रामपुर जिला अधिकारी अजय द्विवेदी ने प्रशासनिक अधिकारीयों निर्देश दिए गए। मृतक एहसान रजा के परिजनों को शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस भेजा गया जिसमें यह मजारे पति-पत्नी और उनके बेटे की बताई जा रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार एहसान रजा गांव में धार्मिक शिक्षा देते थे उनकी मृत्यु लगभग 50 वर्ष पहले हो चुकी थी जबकि उनकी पत्नी का निधन करीब 30 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके बेटे की मृत्यु लगभग 18 वर्ष पहले हुई थी। तीनों को उसी जगह दफनाया गया था जहां एहसान रजा लोगों को दीनी तालीम देते थे। ग्राम प्रधान लाइक ने बताया कि एहसान रजा अपने पिता की इकलौती संतान थे। प्रशासनिक दस्तावेज के अनुसार यह भूमि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान का हिस्सा है इसी आधार पर शिक्षा विभाग के परिजनों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित समय का नोटिस दिया है नोटिस के बाद परिवार की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस संबंध में रामपुर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है उन्होंने कहा है कि पहले यह मदरसा बनाने का प्रयास किया गया था। जिसे हटाया गया था और अब एक स्थान पर तीन मजारे बनी हुई है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जा चुका है और नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद गांव में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेजी हैं कुछ ग्रामीण नाम ना छुपाने की शर्त पर प्रशासन की कार्रवाई के समय पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि लोगों ने एहसान रजा को भी वही दफनाया था। क्योंकि वह अपनी इच्छा व्यक्त करते थे कि उन्हें इसी स्थान पर दफनाया जाए वे तालीम देते थे

संक्षिप्त समाचार

भतीजे ने चाची के पैर में गोली मारी, 3 घायल, वैशाली में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के मझौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला को गोली लग गई। इस घटना में कुल तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि मझौली गांव में आपसी जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। मारपीट के दौरान गोली चलाई गई, जिससे एक महिला के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल महिला की पहचान बिदुपुर थाना के मझौली गांव निवासी रामजी चौधरी की पत्नी गीता देवी (55) के रूप में हुई है। अन्य घायलों में विलाश चौधरी के पुत्र गनौर चौधरी (60) और सुनील चौधरी की पत्नी निभा देवी (25) शामिल हैं। घायल महिला के बेटे पप्पू कुमार ने बताया कि उनके पट्टीदार जागेश्वर चौधरी के पुत्र लालू चौधरी ने अपने ससुराल बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव से लगभग 10 लोगों को बुलाया था। सुबह में इन लोगों ने बांस काटकर डंडे बनाए और करीब 10 बजे अचानक उनके घर पर आकर मारपीट करने लगे। इसी दौरान लालू कुमार ने गोली चला दी, जो उनकी मां के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की और मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

पेड़ लूटने का विरोध, कर्मियों का सिर फोड़ा, 2 मजदूर गंभीर घायल, लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में NH-122 B परियोजना के तहत पेड़ काट रहे कर्मियों पर हमला किया गया। लकड़ी लूटने का विरोध करने पर हुई इस मारपीट में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मनियारपुर स्थित योगी स्थान के पास हुई। परियोजना में आर्बोरिस्ट के पद पर कार्यरत नीरज कुमार तिवारी ने बताया कि उनके मजदूर बिट्टू राज और चंदन कुमार मनियारपुर में पेड़ काटने का काम कर रहे थे। इसी दौरान कैलाश पासवान (लकड़ी कारोबारी), मितल पासवान, सन्नी कुमार, राजन कुमार, कारू कुमार और अभिषेक कुमार सहित 20-25 अज्ञात ग्रामीण जबरन लकड़ी लूटने लगे। मजदूरों और मौके पर मौजूद वन रक्षक ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में मजदूर बिट्टू राज के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि चंदन कुमार भी बुरी तरह घायल हो गए। वन रक्षक पदाधिकारी विकास कुमार ने दोनों घायल मजदूरों को तुरंत बिदुपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नीरज कुमार तिवारी के अनुसार, दोनों मजदूरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। नीरज कुमार तिवारी जब घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे, तो वहां मौजूद चार लोगों ने उन्हें एससी/एसटी एक्ट में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में बिदुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

वैशाली में बाल श्रम से 5 बच्चे बचाए गए, आरोपी को देना होगा 50,000 रुपए तक का जुर्माना

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में बाल श्रम के खिलाफ चलाए गए अभियान में गुरुवार को पांच बच्चों को मुक्त कराया गया। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर धावा दल ने भगवानपुर और गोरौल प्रखंड में यह कार्रवाई की। यह रेस्क्यू ऑपरेशन श्रम संसाधन विभाग वैशाली, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल वैशाली और स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में चलाया गया। मुक्त कराए गए सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहीं, बच्चों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के डायरेक्टर सह सचिव डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाना है। डॉ. शुक्ला ने बताया कि बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। इसके उल्लंघन पर नियोक्ता को 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद का प्रावधान है। मुक्त कराए गए बच्चों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा 3,000 रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में गोरौल और भगवानपुर थाने की पुलिस बल, बचपन बचाओ आंदोलन की अनुपम कुमारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के इंस्पेक्टर याकूब अली, तथा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के प्रतिनिधि नीलू कुमारी, राजीव कुमार और गुड्डू कुमार शामिल थे।

पटना से नेपाल भेजी जानी थी नशीली इंजेक्शन, खेप जब्त, पूर्वी चंपारण के चार तस्कर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के माधौल फोरलेन के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। नशीले इंजेक्शनों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक सूमो वाहन से 4 हजार डायजेपाम और बायप्रो नोर्फिन इंजेक्शन बरामद किए हैं। इस मामले में अंतरजिला गिरोह से जुड़े चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि इंजेक्शन की यह खेप रक्सौल के रास्ते नेपाल भेजी जानी थी। सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप लेकर कुछ लोग रक्सौल की ओर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही माधौल फोरलेन के पास गाड़ी जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध सूमो वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में डायजेपाम और बायप्रो नोर्फिन इंजेक्शन बरामद हुए। बाद में इंजेक्शनों की गिनती कराई गई, जिसमें कुल 4 हजार डायजेपाम इंजेक्शन होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रक्सौल निवासी मो. सलीम और सोनू कुमार और पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र निवासी चूमन राम और मो. आजाद के रूप में हुई है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पटना के नाला रोड इलाके में रहने वाले हरि नाम के व्यक्ति ने उन्हें यह खेप सौंपी थी। इंजेक्शन को रक्सौल पहुंचाना था, जहां से आगे नेपाल भेजे जाने की योजना थी। आरोपियों ने बताया कि इस काम के एवज में उन्हें कुल 10 हजार रुपये मिलने वाले थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी चूमन राम ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वह इससे पहले भी तीन बार इसी तरह नशीले इंजेक्शनों की खेप नेपाल पहुंचा चुका है। इस बयान के बाद पुलिस को अंतरराज्यीय और नेपाल तक फैले तस्करी नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है। अब पुलिस सप्लाई चेन से जुड़े अन्य तस्करों और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना वरीय अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टर को भी दी गई है। बरामद इंजेक्शनों की जांच कराई जा रही है और तकनीकी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर विजय कुमार भारती ने बताया कि डायजेपाम इंजेक्शन का उपयोग गंभीर चिंता, मांसपेशियों में ऐंठन, शराब छोड़ने के दौरान होने वाली समस्याओं और मिर्गी के दौरे के इलाज में किया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय सलाह के बिना या गलत तरीके से इसका इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। अधिक मात्रा में उपयोग करने पर व्यक्ति मानसिक रूप से सुस्त हो सकता है और लगातार दुरुपयोग की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।

पटना में 124 करोड़ से बनेंगे 19 आधुनिक वेंडिंग जोन

म्यूनिसिपल बॉन्ड से मिलेगा फंड, 4400 फुटपाथी वेंडर्स का मिलेगा स्थायी दुकान

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना नगर निगम 124 करोड़ रुपये की लागत से 19 आधुनिक वेंडिंग जोन बनाने जा रहा है। इसके लिए कुल 760.81 डिसमिल जमीन चिन्हित की गई है। इससे 4400 वेंडरों को राहत मिलेगी। प्रत्येक वेंडिंग जोन में 200 से 235 दुकानों की व्यवस्था होगी। भविष्य में कुल 31 वेंडिंग जोन बनाकर 7200 वेंडरों को बसाने का लक्ष्य है। इस पर खर्च होने वाली राशि 200 करोड़ रुपये के म्यूनिशिपल बॉन्ड से जुटाई जाएगी। नगर निगम का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और अगले दो महीने में बॉन्ड जारी होने की उम्मीद है।

नूतन राजधानी और पाटलिपुत्र अंचल में बनेंगे 12 वेंडिंग जोनः अभी चिन्हित 19 वेंडिंग जोन में 9 जगहों पर नगर निगम की अपनी जमीन है, जबकि बाकी 10 जगहों के लिए पथ निर्माण, सिंचाई और भवन निर्माण विभाग से उनके जमीन पर बनाने के लिए NOC के लिए

पत्र लिखा गया था। वर्तमान में सबसे अधिक 8 वेंडिंग जोन नूतन राजधानी अंचल में बनेंगे। नूतन राजधानी और पाटलिपुत्र अंचल में 12 वेंडिंग जोन बनेंगे। नूतन राजधानी अंचल में सबसे ज्यादा 8 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर 61.69 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मल्टीलेवल पार्किंग के पीछे बनेंगे G+1 वेंडिंग जोनः इसके तहत शेखपुरा रैन बसेरा, अमला टोला, पंच मंदिर, इको पार्क डीपीएस के पास, चित्रगुप्त समाज मंदिर, साकेत नगर, बेउर मोड़ व स्टेशन रोड मल्टीलेवल पार्किंग के पीछे G+1 वेंडिंग जोन बनेंगे। वहीं, पाटलिपुत्र अंचल में 24.29 करोड़ की लागत से 4 वेंडिंग जोन प्रस्तावित हैं। इनमें मछली मार्केट के पास आरसीडी की जमीन, वार्ड 20 में सब्जी मार्केट के पास, वार्ड 8 में बीएमएसआइसीएल के सामने और वार्ड 24 में दीघा पोस्ट के सूर्य मंदिर के पास आधुनिक G+1 परिसर तैयार किए जाएंगे।

म्यूनिशिपल बॉन्ड की फंड से तैयार होंगे वेंडिंग जोनः वेंडिंग जोन बनाने में म्यूनिशिपल बॉन्ड का पैसा खर्च किया जायेगा। दरअसल, पटना नगर निगम 200 करोड़ रुपये का म्यूनिशिपल बॉन्ड जारी करने जा रहा है। इसके लिए बाजार नियामक सेबी से हरी झंडी मिल चुकी है और निगम जल्द ही इसका फाइनल प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजने वाला है। बॉन्ड से मिलने वाली राशि को मुख्य रूप से उन योजनाओं में निवेश किया जाएगा, जहां से निगम को स्थायी राजस्व मिल सके और वेंडिंग जोन इसका सबसे बड़ा जरिया बनेंगे।

आधारभूत संरचना विकास योजनाओं की मासिक समीक्षा, गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः आज दिनांक 12.06.2026 को स्थानीय विकास भवन में जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आधारभूत संरचना विकास से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्यों की गुणवत्ता तथा समय पर पूर्णता की स्थिति का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उनके त्वरित समाधान, नियमित निगरानी तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर बल दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा योजनाओं की प्रगति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को विकास कार्यों की गति बनाए रखने एवं निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व पीए के खिलाफ कराया एफआईआर

लोकतंत्र की शान, पटना

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री अशोक चौधरी ने अपने पूर्व निजी सहायक (PA) के खिलाफ पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट का एक्सेस अब भी पूर्व PA निशांत केतु झा के पास है, जबकि वह नौकरी छोड़ चुके हैं।

मंत्री कार्यालय के मुताबिक, पूर्व PA से सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस वापस देने का आग्रह किया गया था, लेकिन आरोप है कि निशांत केतु झा ने इसके बदले पैसे की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि गलत तरीके से मंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को अपने नियंत्रण में रखा गया है।

निशांत केतु झा ने बताया कि, मेरे पर्सनल मेल से ट्विटर अकाउंट अशोक चौधरी जी का बनाया गया

था। अब मेरे ऊपर पर्सनल मेल का एक्सेस देने का दबाव बनाया जा रहा है। भला मैं अपने पर्सनल मेल का एक्सेस कैसे दे सकता हूं। उन्हें अपना चेंज करना है, तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल मेल का जबरन एक्सेस लेने के लिए दबाव देना अनुचित है। निशांत केतु झा ने आगे कहा कि, 'मैं जब तीन साल में कोई दबाव नहीं बनाया। उस मेल से मतलब नहीं रखा तो अब भला क्या रखूंगा। कोई रुपए वगैरह की डिमांड मेरी ओर से नहीं की गई है।' साइबर DYSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि, 'शिकायत दर्ज हो गई है।

सहरसा में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा विभिन्न विभागों में सिपाही पदों पर चयन हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर आज स्थानीय विकास भवन में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का संयुक्त सम्बोधन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने की। यह परीक्षा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के 'मद्य निषेध सिपाही', कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के 'कक्षपाल' तथा परिवहन विभाग के 'चलन्त दस्ता सिपाही' पदों के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक में जानकारी दी गई कि परीक्षा का आयोजन जिले के विभिन्न चिन्हित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 14 जून 2026 एवं 17 जून 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली में रिपोर्टिंग समय

सुबह 8:00 बजे एवं द्वितीय पाली में दोपहर 1:00 बजे तय किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व, अर्थात सुबह 9:00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। परीक्षा के सुचारु एवं कदाचार रहित संचालन हेतु कुल 26 स्टैटिक दंडाधिकारी, 5 जोनल दंडाधिकारी तथा 2 उड़नदस्ता दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्टैटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे, जबकि जोनल दंडाधिकारी गश्ती दल के साथ भ्रमणशील रहकर व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, अपर समाहर्ता (वि० जांच) श्री गणेश कुमार, अपर समाहर्ता श्री निशांत सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 15 ट्रकों सहित कई वाहनों का चालान

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106, 107 एवं 327E पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संचालित किया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। सड़क किनारे खड़े ट्रकों एवं अन्य भारी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 15 ट्रकों का चालान किया गया। साथ ही वाहन चालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने वाहनों की पार्किंग केवल स्वीकृत ले-बाई, वे-साइड एमेनिटीज, पेट्रोल पंप, धर्मकांटा या अन्य निर्धारित स्थलों पर ही करें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लंबे

समय से सड़क किनारे खड़े वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना में जमा कराया जाएगा। अभियान के दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इस क्रम में 10 ऑटो रिक्शा चालकों पर बिना वैध अनुज्ञप्ति वाहन संचालन करने के कारण प्रत्येक पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC), वाहन बीमा, निबंधन प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल एवं चारपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी ट्रक एवं भारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाहन खड़ा न करें, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि वाहन चालक अपने वाहनों को केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। इस अभियान में जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी, मोटरयान निरीक्षक तथा प्रवर्तन दल सक्रिय रूप से शामिल रहे। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

खान सर के गार्ड्स की जमानत याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना सिविल कोर्ट में खान के बॉडी गार्ड्स और ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। खान के दोनों बॉडी गार्ड्स की जमानत पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा के कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है। इससे पहले कहा गया कि खान के वकील की तबियत खराब है, सोमवार को आयेगा। कोर्ट में खान के गार्ड्स के वकील की ओर से दलील दी गई कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों ने फायरिंग की थी, इसलिए बेल रिजेक्ट की जाती है।

वहीं, रौशन आनंद की ओर से जिला जज के यहां बेल फाइल की गई थी, जो ट्रांसफर होकर ADJ 33 के कोर्ट में गया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के वकील ने बहस नहीं की, बल्कि टाइम पीटिशन देकर समय मांग लिया गया। अब

रौशन आनंद की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी।

खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र आज तीसरी बार सड़क पर उतरे। पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई गई। पुलिस ने छात्रों को पटना कॉलेज से आगे जाने की परमिशन नहीं दी।

पटना साहिब जत्थेदार ने की पूर्व-जत्थेदार पर कार्रवाई की मांग

अमृतसर। पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मांग ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा एक दुनियावी जांच एजेंसी (एसआईटी) के समक्ष बयान देने के बाद की गई है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न समाचार चैनलों की रिपोर्टों के अनुसार, ज्ञानी रघबीर सिंह ने एक दुनियावी जांच एजेंसी के सामने बयान दिए हैं। जत्थेदार रंजीत सिंह के अनुसार, यह कार्य श्री अकाल तख्त साहिब की पवित्र परंपराओं, सिख सिद्धांतों और उसकी मर्यादा का उल्लंघन है। ज्ञानी रंजीत सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि श्री अकाल तख्त साहिब दुनियाभर के सिखों के लिए सर्वोच्च धार्मिक संस्था है।

पटना में जलजमाव रोकने की तैयारी तेज

लोकतंत्र की शान, पटना

मानसून से पहले शहर में जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त यशपाल मीणा द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं। ज्ञान भवन और गांधी मैदान परिसर के अंदर स्थित नालों को ह्यूम पाइप बिछाकर जोड़ा जाएगा। नगर आयुक्त ने वार्ड संख्या 24, 25, 26 और 27 का निरीक्षण किया। उन्होंने नौ संवेदनशील स्थलों पर जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय और डीएम आवास के सामने जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की गई। दरअसल, पटना में हुई 1 घंटे की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कई जगह निर्माण कार्य जारी रहने के कारण सड़कों पर जलजमाव और कीचड़ ने लोगों को काफी परेशान किया। सड़कों पर फिसलन होने से बाइक और स्कूटी सवार के एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहा।

क्राइस्ट चर्च स्कूल के पास भूमिगत नाले की होगी सफाईः गांधी मैदान गेट

संख्या-5 के सामने क्राइस्ट चर्च डायोसेसन स्कूल के निकट जलजमाव की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि भूमिगत नाले की सफाई की आवश्यकता है। नगर आयुक्त ने रात्रि में सड़क को नियंत्रित रूप से काटने, नाले की सफाई कराने और तत्पश्चात सड़क को पहले जैसा करने के निर्देश दिए, ताकि यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और जलनिकासी व्यवस्था सुचारु हो सके।

चैंबरों को आपस में लिंक करने के निर्देशः बुद्धा कॉलोनी में एस.के. पुरी पार्क गेट संख्या-8 के सामने दोनों ओर बने चैंबरों

- **ह्यूम पाइप से जुड़ेंगे ज्ञान भवन-गांधी मैदान के नाले, मानसून अलर्ट के लिए कर्मियों को मिलेगी वॉकी-टॉकी**

को आपस में लिंक करने के निर्देश दिए गए ताकि जलनिकासी की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त पार्क के गेट संख्या-1 के सामने स्थित चैंबर को खुलवाकर नाले की उड़ाही की स्थिति की जांच की गई। नगर आयुक्त ने क्षेत्र में तुरंत जलनिकासी सुनिश्चित करने के लिए नाले पर ग्रेटिंग लगाने और आवश्यकतानुसार ह्यूम पाइप लगाने के निर्देश दिए।

गड्ढे को लाल कपड़े से घेरने का निर्देशः मोक्ष द्वार (बांस घाट) के सामने जलनिकासी की धीमी गति को लेकर अधिकारियों ने अवगत कराया कि क्षेत्र का नाला काफी पुराना है, जिसके कारण पानी निकलने में समय लगता है। नगर आयुक्त ने अभियंताओं को नाले की तकनीकी जांच कर बेहतर बनाने के लिए तत्काल कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। दूसरा स्थित श्रीराज अपार्टमेंट (टीसीएस ऑफिस) के समीप निरीक्षण के दौरान नाले के ध्वस्त होने तथा चैंबर के पास गड्ढा पाए जाने पर तत्काल गड्ढे को लाल कपड़े से घेरने, अस्थायी रूप से ह्यूम पाइप लगाकर जलनिकासी सुनिश्चित करने तथा शीघ्र गड्ढे को भरने के निर्देश दिए।

दूसरी ओर बुडको प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर के सभी 91 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन (DPS) पर टीमें 24x7 अलर्ट मोड में तैनात रहेंगी। बुडको के कर्मियों को पटना नगर निगम के साथ समन्वय करके वॉकी टॉकी से जोड़ा गया है, जिससे कहीं परेशानी आने पर अलर्ट रहे। दोनों विभाग वॉकी टॉकी से जुड़े रहे। पटना में वर्तमान में 56 स्थाई और 35 अस्थाई DPS पूरी तरह काम कर रही हैं। जल निकासी के लिए 364 हाई-कैपेसिटी पंप लगातार चलाए जा रहे हैं, जिनमें 265 विद्युत चालित और 99 डीजल पंप शामिल हैं। स्थाई DPS पर 256 पंप और अस्थाई DPS पर 83 पंपों ने बिना रुके काम किया।

संक्षिप्त समाचार

सीधी के छात्र की रेलवे स्टेशन में बेरहमी से पिटाई

लोकतंत्र की शान सीधी। सीधी के एक छात्र की रेलवे स्टेशन रीवा में बेरहमी से मारपीट कर जीआरपी पुलिस द्वारा 5 हजार रुपये छीनने का मामला सामने आया है। पुलिस कर्मियों के इस कृत्य के कारण ट्रेन छूट जाने से छात्र को सामान एवं किताबों से भी हाथ धोना पड़ा। तत्संबंध में पीड़ित छात्र प्रशांत रावत पिता मणिराज कोल निवासी ग्राम बगैहा, गांधी ग्राम ने बताया कि वह इंदौर में आकार कोचिंग इंस्टीट्यूट में राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कुछ दिन पहले अपने गृह ग्राम आया था। कल दिनांक 11 जून 2026 को रात 11 बजे रीवा से अंबेडकर नगर चलने वाली ट्रेन से इंदौर जा रहा था। टिकट न मिलने के कारण जनरल बोगी में बैठा था। ट्रेन लेट थी इस वजह से वहीं नीचे खड़ा था। उसी दौरान रीवा के एक जीआरपी पुलिसकर्मी साथ में एक दबंग व्यक्ति को लेकर पहुंचा और पूंछा क्यों खड़े हो। उनको बताया गया कि इंदौर में कोचिंग पढ़ाई के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर घसीट कर पुलिस कंट्रोल रूम ले गये। वहां मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए अकारण मारपीट कर 5 हजार रुपये छुड़ा लिए। छात्र का चप्पल और मोबाइल रख लिए । छात्र ने काफी आरजू मिन्नत कर कहा कि छोड़ दिया जाये ट्रेन के साथ उसका बैग भी चला जायेगा। किंतु जबरन बैठाकर रखा गया। एक घंटे बाद बड़े अधिकारी के आने के बाद छोड़ा गया। किसी तरह आज सुबह 11 बजे सीधी आया। पीड़ित छात्र ने शासन-प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है।

पानी में डूबने से मृत्यु पर 4 लाख की आर्थिक मदद

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। उपखण्ड अधिकारी राजस्व चुरहट/सीधी ने पानी से डूबने से मृत्यु के मामले में मृतक के पिता को आरबीसी 6(4) के तहत 4 लाख की राहत राशि स्वीकृत किया है। न्यायालय तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्र. 0001/ब-128 (9)/2026-27 प्रतिवेदन दिनांक 2 जून 2026 तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, हल्का पटवारी के प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों के अनुसार दिनांक 7 मई 2026 समय सुबह लगभग 10 बजे विकास सिंह गोड पिता रामसुमिरन गोड उम्र 17 वर्ष की मृत्यु तालाब पानी में डूबने से हो गई है। तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रतिवेदनानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका 5(2क) संशोधित प्रावधान दिनांक 6 दिसंबर 2016 के तहत मृतक विकास सिंह गोड के पिता रामसुमिरन गोड पिता रामसेवक सिंह गोड सा. अमिलई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी को रूपये 4 लाख रूपये मात्र की आर्थिक सहायता राशि बैंक खाता क्रमांक 33371001950 में भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है।

रेवाड़ीः दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हादसे में एचडीएफसी कर्मचारी की मौत

लोकतंत्र की शान : रेवाड़ी। जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरूवार रात हुए सड़क हादसे में एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा धारूहेड़ा क्षेत्र में उस समय हुआ जब एक कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई तथा दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर सुचारु रूप से बहाल कराया। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र यादव महेंद्रगढ़ जिले के गांव गणियार का रहने वाला था। वह एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था और नियमित रूप से अपने कार्यस्थल तक आवागमन करता था। गुरूवार रात वह बाइक से जा रहा था, तभी कार से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे गंभीर चोटें आईं। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों के अनुसार सुरेंद्र यादव की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। उनके परिवार में पत्नी और करीब डेढ़ वर्ष का बेटा है। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

गुरुग्रामः पेट्रोल पंप के पास मिला युवक का शव, करंट से मौत की आशंका

लोकतंत्र की शान : गुरुग्राम। सिकंदरपुर बढ़ा गांव स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान पानीपत जिले के समालखा निवासी पियूष के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी है।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार यह पता लगाया जा रहा है कि युवक किन परिस्थितियों में करंट की चपेट में आया। घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ।

नारनौलः केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रवेश आवेदन तिथि बढ़ी, 19 जून तक मौका

लोकतंत्र की शान : नारनौल। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि) महेंद्रगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 19 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो टंकेशवर कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आवेदन तिथि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह निर्णय विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो 20 और 21 जून को खुली रहेगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों को सुधार सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से करेक्शन विंडो का लाभ उठाकर सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपील की है।

पुताई करने गए दो श्रमिकों ने किया युवती से सामूहिक दुष्कर्म

» घर में अकेले थी पीड़ित युवती

» जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत की हैं यह घटना

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी । जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में घर में पुताई का काम करने आए दो युवकों ने एक लड़की को अकेले पाकर बंधक बना लिया। उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और डरा-धमकाकर ऑनलाइन पैसे भी लूट लिए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। यह खौफनाक घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की है। आरोपी अनूप साकेत और राकेश साकेत पुताई और पेंटिंग के काम के बहाने घर के अंदर आए थे। उस वक्त 20 साल की लड़की घर में बिलकुल अकेली थी। आरोपियों ने इसका फायदा उठाया और लड़की को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने लड़की के ही मोबाइल से 'फोन पे' ऐप के जरिए 40,000 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। कमरे में बंद कर किया सामूहिक दुष्कर्म

पुलिस ने चंद घंटों में दोनों को पकड़ा

शाम को जब परिवार के लोग घर लौटे, तो रोती हुई पीड़ित लड़की ने उन्हें पूरी आपबीती सुनाई। परिवार तुरंत थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रात करीब 8 बजे केस दर्ज किया। सीधी एसपी संतोष कोरी ने बताया कि घटना की खबर मिलते ही पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आई। देर रात ही आरोपियों के छिपने के ठिकानों पर छापेमारी की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया और शाम 5 बजे उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एसपी ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

पैसे लूटने के बाद भी नहीं भरा मन

उन्होंने लड़की को एक कमरे में बंधक बना लिया और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। जब पीड़ित लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की और विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग निकले।

अवैध रेत परिवहन करते हाइवा जब्त, चालक पर मामला दर्ज

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धुम्माडोल में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेत से भरी एक हाइवा बिना नंबर के वाहन जब्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोपद नदी के गुड़ुवाधार क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। बिना देरी करते हुते थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी टीम भेजा मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हाइवा को रोककर जांच की, जहां चालक मानेन्द्र प्रसाद यादव (26 वर्ष), निवासी बारी थाना सेमरिया, रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में चालक ने गोपद नदी से रेत लोड कर विक्रय हेतु ले जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने करीब 35 लाख रुपये मूल्य की हाइवा तथा 20 हजार रुपये मूल्य की रेत सहित कुल 35.20 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 77/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।कार्यवाही में प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिहं ,आरक्षक दिनकर द्विवेदी,अजय विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही है।

कांग्रेस की अंतर्कलह का शिकार हुई मीनाक्षी नटराजनः रीती

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। सीधी विधानसभा की विधायक, वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती रीती पाठक ने राज्यसभा की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने और कांग्रेस द्वारा प्रलाप और हल्ला हो हल्ला करने पर त्वरित टिप्पणियां व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह, अंतर्विरोध, गुटबाजी, लापरवाही, अंदरूनी षड्यंत्र का मीनाक्षी नटराजन शिकार हुई है। विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि बहन मीनाक्षी के प्रति मेरी गहरी संवेदना है किंतु बहन मीनाक्षी नटराजन का कोई पहला उदाहरण नही है। इसके पहले भी कांग्रेसी आपसी खिचतान कर धोषित प्रत्याशियों को मैदान से हटा चुके हैं जिसके प्रमुख उदाहरण गुजरात की सूरत लोकसभा सीट 2024 से नीलेश कुंभानी शिकार हुए, मुकेश दलाल बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हुए, मध्यप्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से 2009 में राजकुमार पटेल, उत्तरप्रदेश की बांसगांव लोकसभा सीट 2019 में कुश सौरभ राव, उत्तरप्रदेश की अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट 2019 में उम्मेद निषाद, महाराष्ट्र की रामटेक लोकसभा सीट से 2019 में रश्मि बर्वे कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह के शिकार हुए और उनके पर्चे और उनका नामांकन रद्द हुआ। सीधी विधायक और पूर्व सांसद श्रीमती रीती पाठक ने कांग्रेस को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि आज कॉंग्रेस की नीति और नीयत देश के सामने स्पष्ट है। नामांकन में पूर्ण जानकारी न देना, कॉंग्रेस नेताओं के आपसी षड्यन्त्र और महिला विरोधी सोच को बताता है। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि देश की जनता जनार्दन को कांग्रेस से सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। ऐ कांग्रेसी जब इनका हित पूरा नहीं होगा, तो वह किसी अन्य का हित नहीं करेंगे।

कटनी जिले के नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा जी से मुलाकात

» पुलिस अधीक्षक महोदय से जिले की भौगोलिक एवं वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर किया पदभार ग्रहण

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी: जिले में नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सर्वप्रथम कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा जी से मुलाकात कर औपचारिक परिचय प्रदान किया। इसके पश्चात उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय से कटनी जिले की वर्तमान भौगोलिक परिदृश्य एवं वर्तमान अपराधिक चुनौतियों तथा प्राथमिकताओं, जिले की कानून व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली की जानकारी ली एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके पश्चात नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पद भार ग्रहण करने के पश्चात कार्यालय की सभी शाखाओं का भ्रमण कर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारी से परिचय प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय, सुशासन, सुरक्षा एवं विश्वास प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। श्री मौर्य ने स्पष्ट किया कि जिले में बेहतर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

50 लाख के चोरी के जेवरात व नकदी बरामद

» चोरी का माल खरीदने वाला ज्वैलर भी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। डांगावास क्षेत्र में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की निशानदेही पर करीब 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं चोरी के जेवरात खरीदने वाले एक ज्वैलर को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार 27 मई 2026 को डांगावास निवासी देवाराम जाट ने मेड़ता सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह सुबह अपने गांव गया हुआ था। दोपहर में वापस लौटने पर उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर रखी अलमारी और बक्सों के ताले भी टूटे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर करीब 34-35 तोला सोने-चांदी के आभूषण तथा 2 लाख 50 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 101/26 धारा 331(3) एवं 305(ए) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने लगातार 12 से 13 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज, फील्ड इंटेलिजेंस, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से गहन जांच की। इसके बाद 9 जून 2026 को मुख्य आरोपी हरदीप सिंह निवासी ढालिया तथा सनी माली निवासी नवां को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और पुलिस रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया गया। बरामदगी में लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात तथा 1 लाख 40 हजार रुपये नकद शामिल हैं। साथ ही चोरी की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चोरी के कुछ सोने के आभूषण हनुमानगढ़ निवासी राकेश सोनी ने खरीदे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राकेश सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से खरीदे गए चोरी के सोने के आभूषण बरामद कर लिए।

गिरफ्तार आरोपी-हरदीप सिंह पुत्र गुरजट, निवासी ढालिया, जिला हनुमानगढ़। सनी पुत्र स्वर्गीय संजीव कुमार, निवासी नवां, जिला हनुमानगढ़। राकेश सोनी पुत्र राधेश्याम, निवासी प्रेमसुख कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन।

बरामद आभूषण-पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सोने का टेवटा, एक जोड़ी सोने की झुमर, एक सोने का राखड़ी सेट, एक सोने की कंठी, एक जोड़ी सोने की पूंचे, एक सोने का मंगलसूत्र, दो सोने की चेन, तीन सोने की अंगूठियां तथा चांदी की चार जोड़ी पायजेब बरामद की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे भी जांच जारी है तथा चोरी के नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस सफल कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है।

धर्मशाला में कथित अवैध तोड़फोड़ और निर्माण को लेकर बवाल

नागरिकों ने नगर पालिका से की तत्काल कार्रवाई की मांग

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़तारोड के सदर बाजार स्थित सुगनचंद केदारनाथ डागा धर्मशाला में कथित रूप से बिना अनुमति चल रही तोड़फोड़ एवं निर्माण गतिविधियों को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को गंभीर बताते हुए नागरिकों ने नगर पालिका मंडल मेड़तारोड के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका की स्वीकृति के बिना धर्मशाला परिसर में प्रवेश कर तोड़फोड़ एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि यह गतिविधि न केवल धर्मशाला की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि भविष्य में किसी बड़े विवाद का कारण भी बन सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

पीडीविभाग विभाग अनियमिताओं का आरोप जांच के कार्रवाई की मांग,तेज

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पीडब्ल्यूडी विभाग चाहे जिले के कोई भी एरिया हो भ्रष्टाचार को लेकर अपने चरम सीमा पर है ठेकेदार हो यह अधिकारी हो एक दूसरे के अपने बड़े अधिकारी मांग पूरी करते हैं जनता का पैसा खुलेआम ठेकेदारों के द्वारा लुटा जा रहा है, -उधर छतरपुर और सागर क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी अधिकारी (c& I) और ठेकेदार की मिली भगत से हुए भ्रष्टाचार और सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं के मामले सामने आए मुख्यC सीपी सिंह और E आशीष भारती के द्वारा ठेकेदारों लाभ पहुंचा कर उनके माध्यमोंसे यह अपनी जेब भरते हैं शासन को नुकसान पहुंच रहे हैं जनता के पैसे का चूना लगाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं घटिया निर्माण बमनोरा -हीरापुर मार्ग बड़ा मलहरा क्षेत्र में हो रहे सड़क पैच वर्क में भारी लापरवाही उजागरहुई थी। निरीक्षण के दौरान घटिया सामग्री और बीटुमान के हाथ लगाते ही उखड़ती की पुष्टि हुई थी जिस पर जन् प्रतिनिधी मैं बड़ी आपत्ति जताई। इधर सरकारी संपत्ति घोटाला छतरपुर लोक निर्माण विभाग पी डब्ल्यू डी के हाउस आप दफ्तरी वाला वर्क में बड़ा खुलासा हुआ था यहां अधिकारी के मिली भगत से रुपए 9 करोड़ की सरकारी

मेड़तारोड में शहरी सेवा शिविर का आगाज़

» पहले दिन अव्यवस्थाओं के बीच लोगों ने सौंपे ज्ञापन

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। राज्य सरकार की ओर से आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेड़तारोड नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार से वार्डवार शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ हुआ। 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पहले ही दिन शिविर में व्यवस्थाओं और समन्वय को लेकर कई सवाल खड़े होते दिखाई दिए।

शिविर में पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग तथा ऊर्जा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया।

प्रचार के अभाव में कम रही लोगों की भागीदारी-शिविर के प्रथम दिन अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि शिविर के संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण कई पात्र नागरिकों को इसकी जानकारी ही नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप शिविर में आमजन की भागीदारी सीमित रही और पहले दिन का असर मिला-जुला नजर आया।

निर्धारित समय पर नहीं शुरू हो सका शिविर-प्रशासन द्वारा शिविर का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से शिविर समय पर शुरू नहीं हो पाया। सुबह 11:30 बजे तक व्यवस्थाएं पूरी तरह नहीं बन सकीं और लगभग 12 बजे जाकर शिविर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। इससे शिविर में पहुंचे लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में प्रचंड और बाबूराम भट्टराई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का परमादेश जारी

काठमांडू। पूर्व बाल सैनिकों से संबंधित मामले में नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को परमादेश जारी किया, जिससे देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों और माओवादी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। माओवादी सशस्त्र सेना में रहे लेनिन बिष्ट और अन्य की ओर से दायर इस याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' और डॉ. बाबूराम भट्टराई को भी प्रतिवादी बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिट याचिका में उठाई गई मांगों के अनुरूप परमादेश जारी किया। लंबे समय से चल रहे इस कानूनी मामले में न्यायालय का यह फैसला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इस फैसले को नेपाल के सशस्त्र संघर्ष के दौरान बाल सैनिकों की भर्ती से जुड़े आरोपों पर आगे कानूनी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसके वास्तविक कानूनी प्रभावों का निर्धारण न्यायालय के पूर्ण फैसले की सामग्री सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लेनिन बिष्ट ने न्याय और पूर्व बाल सैनिकों की एकता के अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिष्ट ने कहा, "पूर्व बाल सैनिकों के लिए न्याय और एकता की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई। आज हमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने परमादेश जारी किया है। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।" उच्चतम न्यायालय ने अभी फैसले का पूर्ण पाठ सार्वजनिक नहीं किया है, जिसकी प्रतीक्षा है।

मप्र के कूनों में चीतों की निगरानी के लिए तैनात जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत

श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए तैनात विशेष रूप से प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत हो गई है। कूनो के डीएफओ और डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कूनो का यह जर्मन शेफर्ड कोई साधारण डॉग नहीं था। जंगल में चीतों की हरकत पर नजर रखने में वन विभाग की मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। डॉग का काम चीतों

की ट्रेकिंग, गश्त के साथ वन अमले की सहायता करना था। बुधवार की शाम को कूनो में ट्रैकिंग डॉग की मौत हुई है। मौत के स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन चीता प्रबंधन की टीम द्वारा प्रारम्भिक तौर पर हार्टअटैक को मृत्यु का कारण मान रहे हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर डॉग के किसी वाहन की चपेट में आने से मौत होने की बात कही जा रही है। कूनो में डॉग की देखरेख के लिए दो हैंडलर तैनात थे। ऐसे में उसकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। कूनो के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल का कहना है कि डॉग की मौत के बाद गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की संभावना जताई जा रही है। उसकी मौत की असली वजह क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।

चुनावी भाषण को लेकर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान को लेकर राजधानी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने एक विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि एक समुदाय एकजुट हो जाए तो वह विरोधियों की "बारह बजा सकता है"। साथ ही उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ भी भड़काया था। इस बयान को लेकर उस समय भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसके पूर्व इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड निवासी तुषारकांति दास ने 20 मई को नेताजीनगर थाने में

शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि भले ही किसी समुदाय का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया हो, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में चुनाव के बाद हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के लिए इस प्रकार के बयान जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी प्रथम दृष्टया उकसाने वाली, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति की प्रतीत होती है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयान से भय, घृणा और गलतफहमी का माहौल बन सकता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इस प्रकार की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान दिया गया यह बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। फिलहाल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में आकाशीय बिजली गिरने से उपसरपंच सहित तीन की मौत, पांच घायल

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में आज शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए है। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कलगांव में आज सुबह मनरेगा में काम करने के दौरान हुई बारिश से बचने के लिए ग्रामीण पेड़ के

नीचे आ गए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए है। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में संतोष पटेल, प्रकाश पटेल, मनराज पटेल (उपसरपंच) सभी कलगांव के निवासी है। सभी के शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया है। अंतागढ़ पुलिस के अनुसर ग्राम कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण का कार्य किया जा रहा था। सभी ग्रामीण काम में लगे हुए थे। यहां पर करीब 70 ग्रामीण काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी, बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास के पेड़ के नीचे आ गये । तभी आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आठ लोग आ गए। इसमें तीन पुरुषों की मौत हो गई और पांच महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया। एक महिला को जिसकी हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिये कांकेर रेफर किया गया है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष विकसित भारत की मजबूत नींव के स्वर्णिम वर्ष

एजेंसी, शिमला

केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अवधि केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्षों का प्रतीक है। भाजपा द्वारा आयोजित "12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" अभियान के तहत शुक्रवार को शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा और संस्कृति दोनों को बदला है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार तक सीमित थी, लेकिन मोदी सरकार ने राजनीति को सेवा, सुशासन और जवाबदेही का माध्यम बनाया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करना ऐसे फैसले हैं, जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण की नीतियों के कारण भाजपा को लगातार तीसरी बार जनता का समर्थन मिला है। देश के अधिकांश नागरिक आज भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में निवास कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान की है। बिलासपुर में एम्स की स्थापना, चंबा, हमीरपुर और नाहन में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं के विस्तार से प्रदेश की तस्वीर बदली है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में 14,400 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल में सभी घरों तक पेयजल सुविधा पहुंचाई गई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख परिवारों को गैस कनेक्शन मिले हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना से एक लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं।

महिंद्रा फाइनेंस ऑफिस सागर में युवक ने खुद को लगाई आग

एजेंसी, सागर

◆ बचाने की कोशिश में ब्रांच मैनेजर भी झुलसा

मध्य प्रदेश के सागर जिले में मकरोनिया थाना क्षेत्र में स्थित महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने दफ्तर के अंदर ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) डालकर आग लगा ली। देखते ही देखते युवक आग की लपटों से घिर गया। उसे बचाने की कोशिश में कंपनी के ब्रांच मैनेजर भी झुलस गए हैं। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी वारदात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

परिजन के अनुसार, राहतगढ़ के रहने वाले नीलेश कुमार जैन ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से एक कार लोन पर ली थी। किन्हीं कारणों से कार की दो किस्तें बकाया थीं। किस्तें न चुकाने के कारण फाइनेंस कंपनी ने कुछ दिनों पहले दमोह से नीलेश की कार को जब्त कर लिया था। नीलेश कुमार जैन के परिजन (साले) नीलेश जैन ने बताया कि कंपनी के लोग घर पहुंच कर पैसा लाए थे। शुक्रवार को नीलेश इसी सिलसिले में अपनी कार वापस लेने और सेटलमेंट की बात करने मकरोनिया स्थित महिंद्रा फाइनेंस के दफ्तर पहुंचे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों और ऑफिस में मौजूद लोगों के मुताबिक, कार्यालय के अंदर नीलेश और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से और अवसाद में आकर युवक ने अपने पास रखी बोतल से खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और माचिस जला ली। पलक झपकते ही युवक के पूरे शरीर में आग लग गई, जिससे पूरे ऑफिस में अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया।

रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के घर पहुंचे बदमाश, दी जान से मारने की धमकी

एजेंसी, बिजनौर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के एक बड़े व्यापारी को कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर रुपये देने की मांग की है । पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को जानकारी देते हुए सुरक्षा और कार्यवाही की मांग की है |

बृहस्पतिवार की रात्रि को व्यापारी विनीत अग्रवाल उर्फ लालू निवासी नई बस्ती के घर पर दो पहिया वाहन से आये चार युवकों ने फोन करके बाहर आने व रुपये नहीं देने पर मारने की बात कही। गली में शोर शराबा सुनकर आसपास के कई लोग भी बाहर आ गये तो चारों युवक व्यापारी को मारने की धमकी देते हुए भाग गये| व्यापारी विनीत अग्रवाल ने 112 डायल पर फोन कर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी के बयान दर्ज किए हैं |

व्यापारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस मामले की लिखित शिकायत करते हुए कहा है कि सत्यम चौधरी , अर्जुन कर्णवाल, गोलू सहित चार युवक मेरे घर आकर जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये की मांग कर रहे थे। रुपए न देने पर मारने की धमकी देकर गए हैं। उन्होंने इन बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है | थाना बिजनौर शहर कोतवाली प्रभारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया की पुलिस क्षेत्राधिकारी को व्यापारी विनीत द्वारा दी गई तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच की जा रही है |

भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है : शुभेंदु अधिकारी

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक समय आधारभूत संरचना विकास के मामले में पिछड़ने वाला भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को दिया। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने देश में हुए आर्थिक और आधारभूत संरचना विकास का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 1317 नए और आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में 164 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस आधुनिक रेल सेवा की पहचान थीं, लेकिन आज वंदे भारत ट्रेनें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी और यात्रा का समय कम हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति भी तेज हुई है।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज उनकी संख्या दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में 90 से अधिक नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। सड़क और परिवहन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में लगभग चार लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया है तथा सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों ने देश की आर्थिक संरचना को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन के मात्र एक महीने के भीतर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण विकास कार्यों में तेजी आई है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी नियमित रूप से दिल्ली जा रहे हैं। इससे विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर आएंगे। उन्होंने बताया कि 20 जून को पहली बार मनाए जाने वाले 'बंगाल स्थापना दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट 9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

एजेंसी, रायपुर

◆ इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का निमंत्रण, आईटी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फार्मा के क्षेत्र में खुली 7,800 रोजगार की राह

छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।

अपराध की जड़ है संस्कारों की कमीः कुमार रणविजय सिंह

एजेंसी, मुरादाबाद

संवेदना वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन समारोह शुक्रवार को रंगारंग संस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं रोज़ देखता हूँ कि अपराध की जड़ संस्कारों की कमी से है। यदि हम बचपन से ही बच्चों को सही-गलत का भेद, अनुशासन और नैतिकता सिखा दें, तो समाज स्वतः सुरक्षित हो जाएगा।

पुलिस अधीक्षक नगर ने आगे कहा कि संवेदना वेलफेयर सोसाइटी का यह संस्कार शिविर समाज निर्माण की दिशा में एक सराहनीय कदम है साथ ही मैं इन बच्चों में कल का अनुशासित और जिम्मेदार भारत देख रहा हूं। विद्यालय की निर्देशिका मेजर डा. मीनू मेहरोत्रा ने कहा कि संस्कार शिविर केवल दस दिन का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन भर की पूँजी है।

विशिष्ट अतिथि के रूप मे कर्मयोगी विद्यापीठ अहमदाबाद से आए स्वामी कृष्णदेव झा ने कहा कि मां बच्चे की पहली गुरु है और उसके दिए संस्कार जीवन की नींव बनाते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कालेज की प्रधानाचार्या सीमा शर्मा ने रामचरितमानस के आदर्शों को जीवन में उतारने पर जोर दिया।

दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मु

एजेंसी, देहरादून

◆ आईएमए की पासिंग आउट परेड में होंगी मुख्य अतिथि
◆ जौलीग्रांट एयर पोर्ट पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री की अगुवाई में स्वागत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंच गईं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी। यहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जून को आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी में 13 जून को आयोजित होने वाली स्प्रिंग टर्म 2026 की पासिंग आउट परेड (पीओपी) में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति परेड की समीक्षा करेंगी और नवप्रशिक्षित कैडेटों को सलामी देंगी। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है व यातायात और ड्रोन प्रतिबंध संबंधी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

मेट्टूर बांध से नहीं छोड़ा गया पानी, कावेरी डेल्टा के 16 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र पर संकट, किसान निराश

एजेंसी, सेलम

तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों को शुक्रवार को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा, जब निर्धारित तिथि 12 जून को मेट्टूर बांध से कुरुवई (प्रारंभिक धान) फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। बांध में जलस्तर और जल भंडारण अपेक्षित स्तर से कम होने के कारण इस वर्ष भी सिंचाई सत्र की शुरुआत समय पर नहीं हो सकी। मेट्टूर बांध कावेरी डेल्टा के 12 जिलों की लगभग 16.05 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए जीवनरेखा माना जाता है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष 12 जून से 28 जनवरी तक डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए बांध से पानी छोड़ा जाता है। इसके लिए बांध का जलस्तर कम से कम 90 फीट और जल प्रवाह पर्याप्त होना आवश्यक माना जाता है, ताकि कुरुवई धान की खेती समय पर शुरू हो सके।

हालांकि इस वर्ष 12 जून को मेट्टूर बांध का जलस्तर केवल 79.62 फीट दर्ज किया गया, जबकि जल प्रवाह महज 424 क्यूसेक रहा। जल भंडारण और आवक दोनों ही अपेक्षा से कम होने के कारण सिंचाई के लिए पानी छोड़ना संभव नहीं हो पाया। इस स्थिति ने कावेरी डेल्टा के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। समय पर पानी नहीं मिलने से कुरुवई फसल की बुवाई प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका असर केवल किसानों पर ही नहीं, बल्कि खेती से जुड़े हजारों कृषि मजदूरों के रोजगार पर भी पड़ेगा। आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद केरल और कर्नाटक के कावेरी जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक का कबिनी बांध भरता है और अतिरिक्त पानी कावेरी नदी के जरिए मेट्टूर बांध तक पहुंचता है। लेकिन इस वर्ष कावेरी बेसिन में अपेक्षित वर्षा नहीं होने से जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं जुट पाया है।

कर्नाटक के 65 फीट ऊंचे कबिनी बांध का वर्तमान जलस्तर 31.84 फीट दर्ज किया गया है। बांध में पानी की आवक 2,446 क्यूसेक है, जबकि कुल जल भंडारण 6.08 टीएमसी है। ऐसे में निकट भविष्य में मेट्टूर बांध को पर्याप्त जल मिलने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। पिछले वर्षों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2023 में मेट्टूर बांध का जलस्तर 103.35 फीट होने के कारण 12 जून को ही कुरुवई खेती के लिए पानी छोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में कमजोर मानसून के चलते जलस्तर तेजी से घट गया और 10 अक्टूबर को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति रोकनी पड़ी थी।

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 ड्राफ्ट : 27 जुलाई 2026 तक सुझाव आमंत्रित- भारत के प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल युग के अनुरूप नियामक क्रांति की ओर एक बड़ा कदम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

- नया मसौदा दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 एक ऐसे नियामक मॉडल की ओर बढ़ता है जो तकनीकी परिवर्तन के साथ कदम मिलाकर चल सके।
- दूरसंचार,मीडिया और डिजिटल संचार से जुड़े कानूनों का लगातार पुनरीक्षण करना, प्रसारण और दूरसंचार क्षेत्र को अधिक पारदर्शी सरल,डिजिटल और व्यवसाय -अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

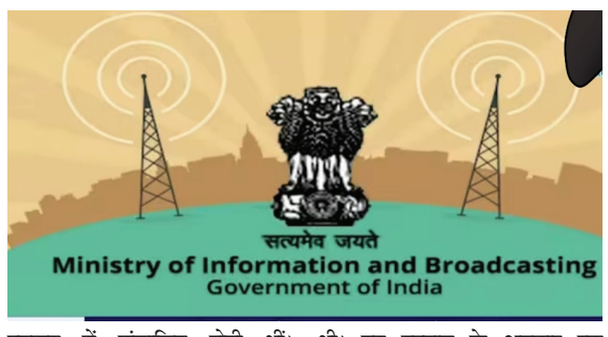

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट आधारित संचार और मीडिया उपभोग के तौर-तरीकों में जिस तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है,उसने सरकारों और नियामक संस्थाओं के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी है कि वे समय -समय पर अपने कानूनों और नियमों को नई परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन करें। कोई भी कानून या विनियामक व्यवस्था स्थायी नहीं होती,क्योंकि तकनीक की प्रगति अक्सर उन परिस्थितियों को बदल देती है जिनके आधार पर कानून बनाए गए थे। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील देश अपने दूरसंचार मीडिया और डिजिटल संचार से जुड़े कानूनों का लगातार पुनरीक्षण कर रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रसारण और दूरसंचार क्षेत्र को अधिक पारदर्शी,सरल, डिजिटल और व्यवसाय- अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।इसी क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है और नागरिकों, उद्योग जगत, विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों से 27 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह पहल केवल नियमों में संशोधन भर नहीं है,बल्कि भारत के प्रसारण क्षेत्र को डिजिटल युग कीआवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने का प्रयास है। इसलिए प्रत्येक नागरिक कार्य कर्तव्य है कि इस दिशा में उनके पास जो सुझाव हाईवे 27 जुलाई 2026 तक संबंधित प्लेटफार्म पर सबमिट करें।भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का नियमन लंबे समय तक 1885 के औपनिवेशिक कालीन टेलीग्राफ अधिनियम के आधार पर संचालित होता रहा।यह अधिनियम उस समय बनाया गया था जब न तो टेलीविजन अस्तित्व में था, न इंटरनेट और न ही डिजिटल मीडिया।स्वतंत्रता के बाद तकनीकी प्रगति के बावजूद कई दशकों तक विभिन्न सेवाओं को अलग- अलग दिशानिर्देशों और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता रहा।परिणामस्वरूप एक जटिल नियामक ढांचा विकसित हुआ जिसमें टेलीविजन चैनलों, डीटीएच सेवाओं, एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो, आईपीटीवी और अन्य प्रसारण सेवाओं के लिए अलग-अलग नियम लागू थे। इससे न केवल उद्योग के लिए अनुपालन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होती थीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी समय लेने वाली और कई बार अस्पष्ट हो जाती थीं। साथियो, दूरसंचार अधिनियम, 2023 इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक विधायी परिवर्तन के रूप में सामने आया था संसद द्वारा पारित यह अधिनियम औपनिवेशिक युग के टेलीग्राफ अधिनियम,1885 का स्थान लेने वाला व्यापक कानून है, जिसका उद्देश्य आधुनिक दूरसंचार और प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र को एक समकालीन कानूनी आधार प्रदान करना है। यह अधिनियम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है और विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अधिकार प्रदान करता है।टेलीविजन,रेडियो और संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रशासकीय प्राधिकरण की भूमिका निभाता है। साथियों, दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का अगला चरण है।इसका मुख्य उद्देश्य उन विभिन्न दिशानिर्देशों को एकीकृत करना है जो अब तक अलग-अलग समय पर जारी किए गए थे और जिनके आधार पर प्रसारण सेवाएं संचालित हो रही थीं। इनमें भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए 2022 की नीति, डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए 2001 के दिशा-निर्देश, एचआईटीएस सेवाओं के लिए 2009 के दिशा-निर्देश, एफएम रेडियो के चरण-III विस्तार संबंधी नीति, सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 2024 के संशोधित दिशा- निर्देश तथा आईपीटीवी सेवाओं के लिए 2008 के दिशा -निर्देश शामिल हैं। इन सभी को एक एकीकृत नियमावली के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है ताकि उद्योग को अलग-अलग नियमों के बजाय एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढांचा प्राप्त हो सके। साथियों, वैश्विक दृष्टि से देखें तो यह कदम भारत को उन देशों की श्रेणी में स्थापित करता है जो नियामक आधुनिकीकरण को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के अनेक देशों ने पिछले दशक में मीडिया और संचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, नियामक सरलीकरण और एकीकृत अनुमोदन प्रणालियों को अपनाया है।भारत द्वारा प्रस्तावित नया ढांचा इसी वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप दिखाई देता है, जहां सरकार का लक्ष्य नियंत्रण और सुविधा के बीच संतुलन स्थापित करना है।मसौदा नियमों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। अब तक प्रसारण सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आवेदन, अनुमतियां और अनुपालन प्रक्रियाएं अलग-अलग स्वरूप में संचालित होती थीं। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत अनेक दिशानिर्देशों को एकल नियामक ढांचे में समाहित कर दिया जाएगा। इससे निवेशकों, प्रसारण कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों को समझना और उनका पालन करना कहीं अधिक सरल हो जाएगा। विशेष रूप से विदेशी निवेशकों और वैश्विक मीडिया कंपनियों के लिए यह स्पष्टता भारत में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। साथियों, नियमों का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण है। डिजिटल शासन आज विश्वभर में प्रशासनिक दक्षता का प्रमुख आधार बन चुका है। यदि अनुमतियां,आवेदन नवीनीकरण और अनुपालन प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित होती हैं तो समय, लागत और मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी आती है। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के संदर्भ में यह कदम प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है।मसौदा नियमों में प्रस्तावित एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार ग्रांट ऑफपरमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता को समाप्त करना है। अब तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और निजी प्रसारकों के बीच अनुमति प्रदान करने के लिए औपचारिक समझौते किए जाते थे। यह प्रक्रिया कई बार अतिरिक्त समय और प्रशासनिक बोझ उत्पन्न करती थी। नए प्रस्ताव के अनुसार इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे अनुमति प्रक्रिया अधिक सरल और डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित हो सकेगी।यह सुधार सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है जिसमें कागजी प्रक्रियाओं को कम करके डिजिटल अनुमोदन प्रणाली को सटीकता से प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, पारदर्शी न्यायनिर्णय तंत्र की स्थापना भी इस मसौदे का एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी नियामक व्यवस्था की सफलता केवल नियम बनाने में नहीं बल्कि उनके निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवर्तन में निहित होती है। प्रसारण क्षेत्र में लाइसेंस, अनुपालन, विवाद और दंड संबंधी मामलों को लेकर समय- समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। यदि एक स्पष्ट और पारदर्शी न्यायनिर्णय प्रणाली स्थापित होती है तो उद्योग और सरकार के बीच विश्वास बढ़ेगा तथा विवादों का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।यह मसौदा नियम केवल उद्योग के लिए ही नहीं बल्किउपभोक्ताओं और नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मीडिया और प्रसारण सेवाएं लोकतांत्रिक समाज में सूचना के प्रसार का प्रमुख माध्यम हैं। जब नियामक व्यवस्था अधिक स्पष्ट और आधुनिक होती है तो सेवा प्रदाताओं को नवाचार करने का अवसर मिलता है।परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं, अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईपीटीवी और नई प्रसारण तकनीकों के विकास के साथ यह अपेक्षा की जा सकती है कि भविष्य में भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक उन्नत मीडिया सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, हाल के वर्षों में भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आधारित टेलीविजन, डिजिटल रेडियो और सैटेलाइट प्रसारण जैसी सेवाओं ने पारंपरिक मीडिया परिदृश्य को बदल दिया है।ऐसे में पुराने नियमों और अलग-अलग दिशानिर्देशों पर आधारित व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकती थी।नया मसौदा इस वास्तविकता को स्वीकार करता है और एक ऐसे नियामक मॉडल की ओर बढ़ता है जो तकनीकी परिवर्तन के साथ कदम मिलाकर चल सके।यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमन, 2026 का मसौदा भी सार्वजनिक किया था। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार और नियामक संस्थाएं केवल उद्योग सुधार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में समानांतर रूप से हो रहे ये सुधार भारत के डिजिटल शासन मॉडल को अधिक उत्तरदायी और आधुनिक बनाने का संकेत देते हैं। साथियों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के दृष्टिकोण से देखें तो नियामक स्पष्टता और प्रक्रियात्मक सरलता किसी भी बाजार की आकर्षण क्षमता को बढ़ाती है। भारत पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। यदि प्रसारण और दूरसंचार क्षेत्र में नियम अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनते हैं तो विदेशी निवेश,तकनीकी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नयन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी हालांकि किसी भी नए नियम की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा नागरिकों,उद्योग प्रतिनिधियों विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करना सहभागी शासन की भावना को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम नियम केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुभव और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा भारत के प्रसारण और मीडिया क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार का संकेत है। यह मसौदा औपनिवेशिक युग की विरासत से निकलकर डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, एकीकृत,पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूलनियामक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है। एकल नियमावली, डिजिटल प्रक्रियाएं, सरलीकृत लाइसेंसिंग, जीओपीए की समाप्ति और पारदर्शी न्यायनिर्णय तंत्र जैसे प्रावधान भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मीडिया एवं संचार बाजार के रूप में स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। यदि सार्वजनिक परामर्श के बाद इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह केवल प्रसारण उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल भारत के व्यापक विजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को संगीत नाटक अकादमी के उपनिदेशक सुमन कुमार ने दी बधाई, लोक संस्कृति के संरक्षण में योगदान को सराहा

- भपंग की थाप से विश्व मंच तक पहुँची मेवात की विरासत, पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी बने लोक परंपराओं के प्रेरणास्रोत

लोकतंत्र की शान

राजस्थान के मेवात अंचल के सुप्रसिद्ध लोकगायक, भपंग वादक एवं "पाण्डून का कड़ा" लोकमहागाथा परंपरा के अग्रणी संवाहक पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को संगीत नाटक अकादमी के उपनिदेशक श्री सुमन कुमार ने पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान कीं। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय लोक संस्कृति और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में गफरुद्दीन जी के योगदान को अद्वितीय और प्रेरणादायक बताया।

मेवाती जोगी समुदाय से संबंध रखने वाले पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी पिछले छह दशकों से अधिक समय से भपंग वादन एवं मौखिक लोकगायन की विलुप्तप्राय परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने पिता एवं गुरु स्वर्गीय बुद्धा सिंह जोगी से भपंग वादन तथा "पाण्डून का कड़ा" की शिक्षा ग्रहण की। महाभारत पर आधारित मेवाती लोकमहागाथा "पाण्डून का कड़ा" भारत की दुर्लभ मौखिक सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है, जिसे भपंग की अनूठी संगति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी इस परंपरा के उन चुनिंदा जीवित प्रतिनिधियों में शामिल हैं, जिनके पास इस विशाल लोकगाथा का प्रामाणिक एवं व्यापक ज्ञान सुरक्षित है। उन्होंने देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों, लोककला महोत्सवों तथा शैक्षणिक आयोजनों में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से मेवात की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच तक पहुँचाया है। उनकी कला ने न केवल लोकसंगीत प्रेमियों को आकर्षित किया है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय लोक संगीत एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2025 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान "पद्मश्री" से अलंकृत किया। संगीत नाटक अकादमी के उपनिदेशक श्री सुमन कुमार ने कहा कि पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी जैसे लोक कलाकार भारत की सांस्कृतिक आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनकी साधना, समर्पण और लोक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। आज पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी भपंग वादन और "पाण्डून का कड़ा" परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जीवित संवाहकों में गिने जाते हैं तथा भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की एक जीवंत मिसाल बने हुए हैं।

एक लोकतंत्र में दो प्रधानमंत्री के 4399 दिन के राजनीतिक महत्व

लेखक - सौरभ वार्ष्णेय

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक विशेष तिथि के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरु के 4,398 दिनों के निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। भारत की राजनीति में कुछ क्षण केवल सांकेतिक नहीं होते, वे इतिहास की दिशा और जनमानस की धारणाओं को भी प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना और जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल की बराबरी करना ऐसा ही एक पड़ाव है। यह तुलना केवल वर्षों की संख्या का खेल नहीं है। नेहरू और मोदी दो अलग-अलग युगों, विचारधाराओं और राजनीतिक शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी दोनों की समानता इस बात में है कि उन्होंने अपने-अपने समय में भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी और देश की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

नेहरू का युग : राष्ट्र-निर्माण की बुनियाद- जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1964 तक लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। उनका दौर विभाजन की त्रासदी, संस्थाओं के निर्माण और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का समय था।नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि उन्होंने नवस्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक ढांचे में स्थिर किया। संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वैज्ञानिक संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ उनके दौर की प्रमुख देन हैं। विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांतों ने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई।हालाँकि नेहरू की नीतियों की आलोचना भी हुई। केंद्रीकृत समाजवादी मॉडल, चीन नीति की विफलता और आर्थिक विकास की धीमी गति उनके आलोचकों के प्रमुख तर्क रहे। फिर भी यह निर्विवाद है कि उन्होंने आधुनिक भारत की बुनियादी संरचना तैयार की।

मोदी का युग : केंद्रीकृत नेतृत्व और नया राजनीतिक विमर्श- नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभरे। 2019 में और फिर 2024 में लगातार जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। तीसरे कार्यकाल के साथ उन्होंने नेहरू के लंबे प्रधानमंत्रित्व की बराबरी कर ली है।मोदी का दौर कई मायनों में नेहरू युग से अलग है। जहाँ नेहरू संस्थाओं के निर्माण और वैचारिक बहुलता के प्रतीक थे, वहीं मोदी मजबूत नेतृत्व, केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया और राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श के प्रतिनिधि माने जाते हैं।मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में डिजिटल इंडिया, आधार आधारित कल्याणकारी वितरण, जीएसटी, बुनियादी ढांचे का विस्तार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, स्वच्छ भारत अभियान और वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय उपस्थिति शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने भी उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत किया।दूसरी ओर आलोचक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक ध्रुवीकरण और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर सवाल उठाते हैं। बेरोजगारी, कृषि संकट और असमानता जैसे मुद्दे भी लगातार बहस के केंद्र में रहे हैं।

क्या केवल कार्यकाल की बराबरी पर्याप्त है?- इतिहास में किसी नेता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होता कि वह कितने समय तक सत्ता में रहा। असली प्रश्न यह है कि उसने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को किस दिशा में बदला। नेहरू ने स्वतंत्र भारत की संस्थागत और वैचारिक नींव रखी। मोदी ने भारतीय राजनीति की शैली और चुनावी संस्कृति को बदल दिया। उन्होंने व्यक्तित्व-आधारित राजनीति, प्रत्यक्ष संचार और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत चुनावी मशीनरी को नई ऊँचाई दी।

दोनों नेताओं के बीच कुछ रोचक समानताएँ भी हैं:

लंबा जनादेश: दोनों को लगातार चुनावी सफलता मिली और जनता ने उन्हें स्थिर नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया।

राष्ट्रीय स्तर की राजनीति: दोनों ने क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर अखिल भारतीय नेतृत्व स्थापित किया।

व्यक्तित्व का प्रभाव: कांग्रेस में नेहरू और भाजपा में मोदी, दोनों अपनी-अपनी पार्टी की राजनीति के केंद्र रहे।

लेकिन अंतर अधिक गहरे हैं। नेहरू का जोर संस्थागत लोकतंत्र और वैचारिक बहस पर था, जबकि मोदी का मॉडल तेज निर्णय, राजनीतिक केंद्रीकरण और चुनावी दक्षता पर आधारित माना जाता है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या अर्थ है?- मोदी का नेहरू की बराबरी तक पहुँचना भारतीय लोकतंत्र की एक दिलचस्प विशेषता को भी उजागर करता है—यह व्यवस्था लंबे समय तक लोकप्रिय नेताओं को अवसर देती है, लेकिन अंततः उनका मूल्यांकन जनता ही करती है। यह पड़ाव भाजपा के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। पार्टी इसे कांग्रेस के ऐतिहासिक वर्चस्व के अंत और नए राजनीतिक युग की पुष्टि के रूप में पेश करेगी। वहीं विपक्ष के लिए यह संकेत है कि केवल सत्ता-विरोधी भावना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक राष्ट्रीय दृष्टि भी जरूरी है। लोकतंत्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत नेतृत्व और मजबूत संस्थाएँ साथ-साथ चलें। इतिहास बताता है कि किसी भी लोकतंत्र की स्थिरता केवल लोकप्रिय नेताओं पर नहीं, बल्कि संस्थागत संतुलन, जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रताओं पर निर्भर करती है। नरेंद्र मोदी का नेहरू की बराबरी तक पहुँचना भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। यह उनके लंबे राजनीतिक प्रभाव और जनता से मिले निरंतर समर्थन का प्रमाण है। लेकिन इतिहास की अंतिम कसौटी केवल अवधि नहीं, बल्कि विरासत होती है। नेहरू को आधुनिक भारत की नींव रखने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है। मोदी की विरासत का आकलन आने वाले वर्षों में इस आधार पर होगा कि उनका नेतृत्व भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक समरसता और आर्थिक दिशा को किस रूप में प्रभावित करता है। बराबरी कार्यकाल की हो सकती है; विरासत की तुलना इतिहास धीरे-धीरे तय करता है।

बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अस्तित्व की लड़ाई में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस

लेखक - कांतिलाल मांडोत

घटते जनाधार और बदलती परिस्थितियों ने बढ़ाई नजदीकियां दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात तथा उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई बातचीत ने राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इन बैठकों को लेकर भले ही किसी भी पक्ष ने औपचारिक रूप से किसी गठबंधन या विलय की संभावना की पुष्टि नहीं की हो, लेकिन राजनीति में संकेतों का महत्व हमेशा शब्दों से अधिक माना जाता है। विशेष रूप से तब, जब दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हों। ऐसे समय में लगातार हो रही मुलाकातें केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं मानी जा सकतीं। इनके पीछे बदलते राजनीतिक समीकरणों और भविष्य की रणनीतियों की झलक भी दिखाई देती है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस कभी देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और लंबे समय तक केंद्र तथा राज्यों में सत्ता के कारण कांग्रेस का प्रभाव लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन पिछले एक दशक में पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। कई राज्यों में उसका संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अब मुख्य राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या पहले की तुलना में काफी घट चुकी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि वह भाजपा के उभार के सामने एक प्रभावी वैकल्पिक राजनीतिक कथा प्रस्तुत नहीं कर सकी। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई। कहीं जातीय राजनीति ने जगह बनाई तो कहीं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ा। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक सिमटता गया। हालांकि राहुल गांधी की यात्राओं और विपक्षी एकता के प्रयासों ने पार्टी को कुछ हद तक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनाए रखा, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस अभी तक अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सकी है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तीन दशक से अधिक समय तक सत्ता में रही वामपंथी सरकार को हटाकर एक नई राजनीतिक शक्ति खड़ी की थी। बाद में उन्होंने भाजपा की चुनौती का भी सफलतापूर्वक मुकाबला किया। एक समय ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस केवल बंगाल तक सीमित पार्टी नहीं रहेगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोवा, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में पार्टी ने विस्तार की कोशिशें भी कीं। लेकिन राजनीति में सफलता स्थायी नहीं होती। यदि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता है, तो यह उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। किसी भी क्षेत्रीय दल की ताकत उसके मजबूत संगठन और निर्विवाद नेतृत्व पर आधारित होती है। जब संगठन में टूट-फूट शुरू होती है और नेताओं का विश्वास डगमगाने लगता है, तब राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी तलाशना एक व्यावहारिक राजनीतिक विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात को केवल एक सामान्य राजनीतिक बैठक के रूप में नहीं देखा जा रहा। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है और तृणमूल कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। दोनों दलों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी चिंता एक जैसी है—राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखना। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संबंधों का इतिहास भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेस की ही उपज हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और बाद में बंगाल की राजनीति में कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। लंबे समय तक दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और अविश्वास का माहौल रहा। कई चुनावों में दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। इसलिए आज यदि दोनों दलों के बीच संवाद बढ़ रहा है तो यह केवल वैचारिक निकटता का परिणाम नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता का संकेत भी माना जा सकता है। राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होते। परिस्थितियां बदलती हैं तो रणनीतियां भी बदलती हैं। यदि कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ बेहतर तालमेल के बिना भाजपा का मुकाबला कठिन है, तो वह पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ सकती है। इसी प्रकार यदि तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है, तो वह भी पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।

फीफा वर्ल्ड कप

डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे चुनिंदा मुकाबलों का मुफ्त टेलीकास्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून की देर रात (भारतीय समय के अनुसार) से होगी। भले ही भारत इस विश्व कप में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन देश में फीफा विश्व कप को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। फैंस 'जी नेटवर्क' पर इन मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ मुकाबले 'डीडी स्पोर्ट्स' पर मुफ्त में देख सकेंगे। मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच ओपनिंग मैच 11 जून की देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल 10 से 12 जुलाई के बीच आयोजित होंगे, जबकि सेमीफाइनल 15 और 16 जुलाई को टेलीकास्ट होंगे। फाइनल 20 जुलाई को होगा। फुटबॉल के इस महाकुंभ में कुल 48 टीमें ट्रॉफी के लिए मुकाबला करते नजर आएंगे। इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका मिलकर करेंगे, जिसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इस नए फॉर्मेट में चार-चार टीमों के 12 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ 8 सबसे अच्छी टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी, जिससे पारंपरिक 'राउंड ऑफ 16' से पहले एक नया 'राउंड ऑफ 32' बनेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरु

जूलियन ने रचा इतिहास, दागा सबसे तेज गोल

पहले मैच में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को हराया

जूलियन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के आठवें मिनट में मेक्सिको के लिए पहला गोल किया। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी ओपनिंग मैच में किया गया अब तक का सबसे तेज गोल रहा।

मैक्सिको (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 के अंतर से हरा दिया। घरेलू टीम के लिए ये एक बड़ी जीत रही क्योंकि इससे ग्रुप ए के राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने की उनकी उम्मीदें बढ़ गई। इस मुकाबले में मेक्सिको का खेल काफी अटैकिंग था वहीं जूलियन क्विनोन्स ने अपनी टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। जूलियन क्विनोन्स ने इस मैच के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो 96 साल के फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत के बाद से अब तक कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया था। जूलियन क्विनोन्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के 8वें मिनट में मेक्सिको के लिए पहला गोल किया। उन्होंने अफ्रीकी टीम के डिफेंस की एक बड़ी गलती का फायदा उठाया और बॉक्स के ठीक बाहर से एक जबरदस्त शॉट मारकर सीधे गोल किया। ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल था।

जूलियन ने रचा इतिहास

इस गोल के साथ जूलियन क्विनोन्स फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी सीजन में पहला गोल करने वाले नॉर्थ अमेरिकन देश के पहले खिलाड़ी बन गए। दरअसल मेक्सिको एकमात्र नॉर्थ अमेरिकन देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच खेला है। उन्होंने पिछले एडिशन (1930, 1950, 2010) में भी ऐसा किया था लेकिन तीनों मौकों पर वे मैच का पहला गोल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे।

जूलियन ने दागा सबसे तेज गोल- जूलियन क्विनोन्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने मैच के आठवें मिनट में मेक्सिको के लिए पहला गोल किया। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी ओपनिंग मैच में किया गया अब तक का सबसे तेज गोल रहा। इस मेक्सिकन विंगर ने जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ी फिलिप लैम का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2006 फीफा वर्ल्ड कप में बोलीविया के खिलाफ 11वें मिनट में पहला गोल किया था।

जीत के साथ दक्षिण कोरिया का आगाज

रोमांचक मुकाबले में चेकिया को 2-1 से हराया

नई दिल्ली । फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत साउथ कोरिया ने जीत के साथ की है। रोमांच के भरपूर मुकाबले में टीम ने चेकिया को 2-1 से हराया। साउथ कोरिया ने मैच के दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। मैच के आगाज के साथ ही साउथ कोरिया और चेकिया की टीम को शुरुआत में गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमें इस भुनाने में नाकाम रहीं। मैच के 9वें मिनट में साउथ कोरिया के पास मिली फ्री किक से बढ़त बनाने का शानदार मौका था, लेकिन चेकिया के डिफेंस ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। 11वें मिनट में साउथ कोरिया की टीम कॉर्नर का भी फायदा उठाने में नाकाम रही। पहले हाफ में कोरिया ने चेकिया के डिफेंस पर दबाव तो खूब डाला, लेकिन उनके डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। चेकिया को पहले हाफ में दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर सकीं। हालांकि, दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में सफलता हाथ लगी। लाडिसलाव क्रेजकी ने बेहतरीन हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

हालांकि, 0-1 से पिछड़ने के बाद साउथ कोरिया ने मैच में शानदार वापसी की। 67वें मिनट में हांग इन बियोम ने टीम की ओर से पहला गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद 80वें मिनट में ओह हियोन ग्यू ने साउथ कोरिया को मुकाबले में लीड दिला दी।

मैच में 2-1 की बढ़त बनाने के बाद साउथ कोरिया ने चेकिया को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया।

349 रन बनाकर भी कैसे हारी इंडिया ए, यह 15 रन पड़ गए भारी

तिलक-ऋतुराज-प्रभसिमरन की पारियां बेकार

नई दिल्ली। इंडिया ए टीम को वनडे त्रिकोणीय श्रंखला म (11 जून) को अफगानिस्तान ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम इस मैच में 349 रन बनाकर भी हार गई। एक तरफ जहां मौसम ने भारत का साथ नहीं दिया और डकवर्थ लुईस प्रणाली से अफगान टीम जीत गई। वहीं इंडिया ए की टीम को 15 रन भी भारी पड़ गए जो आखिरी में हार का बड़ा कारण बने।

आपको बता दें कि बारिश से प्रभावित इस मैच में पहले लक्ष्य को और ओवर को घटाया गया और अफगानिस्तान ए को 38 ओवर में 294 का टारगेट मिला। फिर बारिश ने बाधा डाली और 25.5 ओवर के बाद खेल रुका जब अफगान टीम के 177 रन दो विकेट पर थे। डीएलएस पार स्कोर से अफगानिस्तान ए की टीम 3 रन से आगे थे। यही कारण है कि भारतीय टीम को हार मिली। इस पारी में भारतीय गेंदबाजों ने 15 रन एक्स्ट्रा के दिए। यही 15 रन अंत में इंडिया ए को मिली हार के बाद सबसे महंगे साबित हुए। भारतीय गेंदबाजों ने 25.5 ओवर की अफगान पारी में ही 15 अतिरिक्त रन खर्च कर दिए। इसमें 8 वाइड थीं और 7 रन लेग बाय के थे। यह 15 रन अगर बचे होते तो शायद इंडिया ए की टीम डकवर्थ लुईस से भी यह मुकाबला नहीं गंवाती।

अफगानिस्तान की अच्छी बल्लेबाजी- अफगानिस्तान की शुरुआत इस मैच में अच्छी रही। हसन ईसाखिल ने तेज बल्लेबाजी की और 29 गेंद पर 34 रन बनाए। उन्होंने शुरू से ही रनरेट बढ़ा कर रखा। दूसरे ओपनर कप्तान इमरान मीर एक छोर पर डटे रहे और 75 रन बनाकर नाबाद रहे। चौथे नंबर पर आए बाहिर शाह ने भी नाबाद 51 रन बनाए।

व्यापार

175 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील, कंपनी के शेयरों में करीब 9 प्रतिशत की तेजी

नईदिल्ली, एजेंसी। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह 175 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील है। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 434.80 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 8.8 प्रतिशत की तेजी के साथ 455 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। एक्सचेंज के डाटा के अनुसार विधी एस खांडेवाल ने 44.87 लाख शेयर के बेच दिए हैं। प्रमोटर ने 390 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों की बिक्री की है। इस ब्लॉक डील की कुल वैल्यू 175 करोड़ रुपये की है। ब्लॉक डील गुरुवार को हुई थी। बता दें, प्रमोटर से 6.41 लाख शेयर खरीदे हैं। वहीं, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने भी शेयरों को खरीदा है। इनके अलावा भी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल की है। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अबतक यह स्टॉक 38 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 53 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 485.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 239 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 4800 करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में कंपनी के शेयरों का कवरेज को स्टार्ट किया है। मौजूदा समय में कंपनी की 46 देशों में हिस्सेदारी है। कंपनी अपने रेवन्यू का 95 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स और बिजनेस टू बिजनेस के जरिए इकट्ठा करती है।

रिलायंस, वेदांता, अडानी... चीन को रोकने के लिए साथ आई भारत की त्रिमूर्ति

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मुकेश अंबानी की रिलायंस, अनिल अग्रवाल की वेदांता और गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत के इन तीनों बड़े औद्योगिक घरानों का उद्देश्य रेयर अर्थ के क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को तोड़ना है। रॉयटर्स के मुताबिक ये तीनों दिग्गज कंपनियां आंध्र प्रदेश में इन महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश में सुविधाएं स्थापित करने के लिए करीब 10 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें ये तीन प्रमुख ग्रुप शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के पास इन दुर्लभ खनिजों का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जो भविष्य की तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। एक सरकारी मसौदा दस्तावेज के अनुसार आंध्र प्रदेश के पास 16 चिन्हित तटीय क्षेत्रों में दुर्लभ खनिजों सहित 211 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र तट की रेत के खनिज संसाधन मौजूद हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में 482.6 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी अयस्क के संसाधन हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 10 साल में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और टाइटेनियम के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। इसी साल फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को उन चार राज्यों में शामिल किया गया था, जहां माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन को कवर करने वाले रेयर अर्थ कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे। इससे पहले नवंबर में केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7300 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी।

टाटा स्टील पर ब्रोकरेज का फोकस

टाटा स्टील के शेयर पर फिदा है ब्रोकरेज, 235 रुपये का दिया टारगेट प्राइस

नईदिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा स्टील के शेयर में भले ही सुस्त माहौल हो लेकिन इसको लेकर ब्रोकरेज बुलिश हैं। ब्रोकरेज एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने मेटल्स और

माइनिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ स्टील कंपनियों का जिक्र किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि वह उन स्टील कंपनियों को प्राथमिकता देती है जिनकी बाजार में मजबूत पकड़ है और जिनका रॉ मटीरियल इंटीग्रेशन बेहतर है। ये वो कंपनियां हैं जिनका कर्ज कम है और जिनकी घरेलू बाजार में अच्छी-खासी मौजूदगी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 75 प्रतिशत फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं और वह अपने 5 एमटीपीए कलिंगनगर ब्लास्ट फर्नेस और 2.2 एमटीपीए कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्स की क्षमता बढ़ा रही है। एंटीक ने कहा कि टाटा स्टील ने लागत कम करने के कई कदम उठाए हैं। इससे बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोकिंग कोल की ज्यादा लागत से इस फायदे पर कुछ असर पड़ सकता है। टाटा स्टील के शेयर की बात करें तो 198 रुपये पर है। ब्रोकरेज एंटीक ने टाटा स्टील शेयर के लिए टारगेट ?235 दिया है। बता दें कि 15 मई को शेयर 224.40 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर का 52 वीक लो 149.70 रुपये है। इस बीच, खबर है कि टाटा स्टील की ब्रिटेन में 1.25 अरब पाउंड की कम कॉर्बन उत्सर्जन की स्टील परियोजना की समयसीमा छह से आठ महीने तक आगे खिसक सकती है। कंपनी को परियोजना के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि टाटा स्टील ब्रिटेन के पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 32 लाख टन क्षमता वाला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) स्थापित कर रही है। यह प्लांट पुराने ब्लास्ट फर्नेस की जगह लेगा और कंपनी की कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) कौशिक चटर्जी ने बताया कि टाटा स्टील ब्रिटेन सरकार, राष्ट्रीय ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर (ईएसओ) के साथ मिलकर इस देरी के प्रभाव को कम करने के प्रयास कर रही है।

एलन मस्क पर 'स्पेस' से डॉलर की बारिश, नेटवर्थ 971 अरब डॉलर, कई देशों की जीडीपी से अधिक हुई दौलत

नईदिल्ली, एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में ऐसा उछाल आया है जिसने अरबपतियों की दुनिया के सारे रिकॉर्ड हिला दिए हैं। एलन मस्क पर 'स्पेस' से डॉलर की इतनी बारिश हुई कि एक ही दिन में उनकी दौलत में 274 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह रकम कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। अगर मस्क के नेटवर्थ की बात करें तो वह खरबपति बनने से केवल 29 अरब डॉलर दूर हैं। उनकी संपत्ति में यह उछाल उनके स्केक्स के आईपीओ से आया है।

अगर दुनिया के कई देशों की जीडीपी से तुलना करें तो मस्क के पास आयरलैंड (779.38 अरब डॉलर), बेल्जियम (776.73 अरब डॉलर), स्वीडन (760.48 अरब डॉलर), इजरायल (719.85 अरब डॉलर), अर्जेंटिना (688.38 अरब डॉलर) की जीडीपी से भी अधिक है। भारत के कई राज्यों सालाना बजट से कई गुना है मस्क की 1 दिन

की कमाई मस्क की सिर्फ एक महीने की 274 अरब डॉलर की संपत्ति वृद्धि भारतीय रुपये में करीब 26.27 लाख करोड़ रुपये बैठती है। यह रकम भारत के कई राज्यों के वार्षिक बजट से कई गुना अधिक है। तुलना करें तो यह राशि भारत की कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप के बराबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत से ही उनकी संपत्ति में 351 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है, जो 56.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस चौंकाने वाली छलांग के पीछे सबसे बड़ी वजह मस्क की अंतरिक्ष कंपनी है। जून 2026 में के शेयरों का वैल्युएशन 135 डॉलर प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर किया गया, जिससे मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य अचानक बढ़ गया। इसके अलावा मई 2026 में से जुड़ी 45 अरब डॉलर की लायबिलिटी को उनकी नेटवर्थ गणना से हटा दिया गया। इससे भी उनकी कुल संपत्ति में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई। मस्क के पास लगभग 4.76 अरब शेयर हैं। कंपनी के नए वैल्युएशन ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं और कंपनी में उनकी करीब 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

दक्षिण अफ्रीका से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर

1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क ने 10 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था। 12 साल की उम्र में उन्होंने नाम का वीडियो गेम बनाया और बेच दिया। इसके बाद कंपनियों के जरिए उन्होंने तकनीक, ऊर्जा, पेमेंट और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। प्राइस के आधार पर मार्केट कैप 1.77 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है, जबकि स्टॉक ऑप्शन और अन्य हिस्सेदारी को जोड़ने पर इसका पूर्ण मूल्यांकन करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर बैठता है। इस वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में शामिल हो गई है और इसका साइज एलन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला से भी बड़ा हो गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)